



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र  
(विधान मंडल सहित)  
का वर्ष 2024-2025 का बजट

**निर्मला सीतारामन**  
वित्त मंत्री  
का  
भाषण

**Budget 2024-2025 of the  
Union Territory of Jammu & Kashmir  
(With Legislature)**

**SPEECH  
OF  
NIRMALA SITHARAMAN  
MINISTER OF FINANCE**

**जुलाई / July 23, 2024**

**जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र  
(विधानमंडल के साथ)**

**का**

**बजट 2024-25**

**वित्त मंत्री**

**निर्मला सीतारामन**

**का भाषण**

**अध्यक्ष महोदय,**

1. मैं इस सम्मानीय सभा के समक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट रखते हुए सम्मानित महसूस कर रही हूँ। अगस्त, 2019 में शुरू किए गए ऐतिहासिक सुधारों के बाद से जम्मू और कश्मीर ने अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक विकास देखा है। इन सुधारों से प्रेरित होकर, संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए त्वरित और समावेशी विकास का मार्ग अपनाया है। इसने संपूर्ण शासन को शामिल करते हुए उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित की है - जिसमें विकासात्मक गतिविधियां, लोक प्रशासन और सुरक्षा के मामले शामिल हैं - जिसने जाति, पंथ या धर्म का विचार किए बिना प्रत्येक निवासी को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
2. 2019 के बाद से, पूरे क्षेत्र ने शांति, प्रगति और समृद्धि का युग देखा है। जम्मू-कश्मीर में तीन दशक से अधिक समय की अशांति के बाद जनजीवन सामान्य हो गया है। गत चार वर्षों से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक संस्थान बिना किसी हड़ताल या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। दैनिक हड़ताल, हड़ताल, पथराव और बंद जैसी पूर्व प्रथाएं अब अतीत की बातें हो गई हैं।
3. इसने यहां के नागरिकों को अपनी अप्रयुक्त क्षमता को जानने, युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने और विकास यात्रा में पूरे दिल से योगदान करने में भी सक्षम बनाया है। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में

उत्साहपूर्वक भाग लिया था। रिकॉर्ड मतदान चुनावों के सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष संचालन, मजबूत लोकतांत्रिक भावना और लोगों की नागरिक भागीदारी के साथ-साथ वर्ष 2019 में शुरू किए गए सुधारों की सफलता का प्रमाण है। संसदीय चुनावों के दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जम्मू-कश्मीर के लोगों की अभूतपूर्व भागीदारी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दशकों की उथल-पुथल के बाद, लोग अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक और अनुकूल वातावरण देख रहे हैं।

4. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि जम्मू और कश्मीर सही मार्ग पर है और सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के रूप में उभरेगा और हमारे भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न में भरपूर योगदान देगा।

### **कानून और व्यवस्था के परिदृश्य में पूर्ण सफलता**

5. संघ राज्य क्षेत्र सरकार आतंक प्रायोजित इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और सुरक्षा बलों ने छद्म युद्ध प्रायोजित करने वालों के बार-बार के प्रयासों को विफल कर दिया है। सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयासों और बलिदान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट, साहसी और अनुशासित रहने के हमारे समाज के आत्मविश्वास और संकल्प को बढ़ाया है।
6. आतंकवाद से लड़ते हुए, सरकार ने जम्मू-कश्मीर में समग्र कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का परिभाषित अभिलक्षण जिसका आम नागरिकों के दैनिक जीवन पर सीधा असर पड़ता है, 'सड़क पर हिंसा' है जो 2019 से पहले एक व्यवस्थित और नियमित घटना थी। आतंकवादी और अलगाववादी नेटवर्कों द्वारा संचालित और नियोजित सड़क पर हिंसा अब अतीत की बात है। छात्र खुश हैं क्योंकि स्कूल बंद नहीं हैं, व्यवसायी खुश हैं क्योंकि अब बंद और हड़ताल नहीं हैं, युवा खुश हैं क्योंकि शांति बहुत सारे आर्थिक अवसर ला रही है, माताएं खुश हैं क्योंकि उनके बच्चे अब सुरक्षित हैं, नागरिक खुश हैं कि अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन, नागरिक सेवाएं आदि जैसी सभी सेवाएं अब उनकी पहुंच के भीतर हैं। इस सामंजस्यपूर्ण कानून और व्यवस्था

की स्थिति ने सरकार को सामाजिक-आर्थिक विकास शुरू करने और लागू करने में मदद की है।

## राजकोषीय स्थिति में सुधार

7. अध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर की राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण करते समय हमने पाया कि वित्तीय प्रबंधन में ऐतिहासिक चुनौतियों के कारण, इसकी विरासत बहुत अधिक राजकोषीय दबाव की है। यह प्रमुख व्ययों की प्रतिबद्ध प्रकृति से बढ़ जाता है जो इसके राजस्व में आनुपातिक वृद्धि द्वारा समर्थित नहीं है। केंद्रीय अनुदान पर इसकी निर्भरता कुल व्यय का लगभग 70% है। निरंतर राजकोषीय दबाव के कारण अर्थोपाय संबंधी अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट का बार-बार उपयोग किया जाता है।
8. इस वर्ष भारत सरकार ने निरंतर राजकोषीय संकट से बाहर आने के लिए जम्मू और कश्मीर में सुधारों के कार्यान्वयन के साथ-साथ पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करके इस ऐतिहासिक विचलन को ठीक करने का निर्णय लिया। मुझे यहां यह उल्लेख करते हुए खुशी हो रही है कि जम्मू-कश्मीर के जटिल राजकोषीय मुद्दों को ठीक करने के लिए 17,000 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता तैयार की गई है।
9. यह देखा गया है कि जम्मू और कश्मीर के बजट का लगभग 11% पुलिस के लिए उपयोग किया जाता है। पुलिसिंग पर इस तरह के खर्च अपरिहार्य होने के कारण, विकास और कल्याणकारी परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए सीमित गुंजाइश बचती है। मुझे इस महती सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्र सरकार जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से पुलिस के बजट का पूरा भार लेने के लिए सहमत हो गई है। केन्द्र सरकार अब जम्मू-कश्मीर पुलिस के वेतन, पेंशन और अन्य खर्चों का वहन करेगी, जिसके लिए वार्षिक बजट में 12,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
10. इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में 5,000 करोड़ रुपये का एकमुश्त विशेष अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

11. इस 17,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात लक्ष्य के भीतर 3.0% होगा। इस अभूतपूर्व सहायता से राजकोषीय स्थिति में पूर्ण सुधार होगा जिससे जम्मूकश्मीर सरकार वित्तीय चुनौतियों की विरासत को सही करने और स्थिर वित्तीय स्थिति बनाए रखते हुए लोगों की विकासात्मक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने में सक्षम होगी।
12. अध्यक्ष महोदय, 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर बैंक का पूर्ण कायापलट सफलता की एक कहानी है। जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रमोटर होने के नाते संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने अपनी पूंजी पर्याप्तता और कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार करने का प्रयास किया है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने शक्ति के संकेद्रण को सीमित करने, प्रबंधन के व्यावसायीकरण और बोर्ड में पेशेवर विशेषज्ञों को शामिल करने संबंधी सुधारों को सुकर बनाया। जब वित्तीय अनुशासनहीनता और परिणामस्वरूप उच्च एनपीए के कारण बैंक को नुकसान हुआ तो संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने 2019 से 2022 तक पर्याप्त इक्विटी पूंजी लगाकर बैंक को सुदृढ़ किया। इन कदमों ने बैंक की वित्तीय स्थिति में बदलाव लाने में मदद की और इसके कारोबार में वृद्धि तथा 2019 से पहले के घाटे से बाहर निकलने में मदद की। सरकार द्वारा सुगम किए गए सुधारों की सफलता बैंक के कारोबारी परिणामों और पिछले पांच वर्षों में इसके कायापलट में अनुकरणीय है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने बैंक की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए पेंशन अतिदेय को समाप्त करने का फैसला किया है।
13. संघ राज्य क्षेत्र ने पिछले पांच वर्षों में गहन सुधारात्मक, सकारात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन देखे हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार "सुधार, निष्पादन और परिवर्तन" के मंत्र पर काम कर रही है। इससे आर्थिक और औद्योगिक क्षमता का उपयोग करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, सामाजिक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, कानून और व्यवस्था मशीनरी को मजबूत करने, शासन प्रणालियों का विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक व्यय की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने, राजस्व सृजन बढ़ाने, व्यर्थ व्यय को कम करने और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने के लिए कई पथ-प्रदर्शक पहल की गई हैं। इनमें से कुछ का निम्नलिखित पैराग्राफ में विवरण दिया गया है:

## शासन में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार

14. सरकार ने अनुमोदन, बोली और निष्पादन प्रक्रियाओं में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य वित्तीय नियमों को अपनाया है। बीईएमएस (बजट, अनुमान, आवंटन और निगरानी प्रणाली) मंच के माध्यम से निधियों का कार्य-वार आवंटन सुनिश्चित करके वित्तीय प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए आईटी सुधार शुरू किए गए थे। हमने प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी खरीद को सक्षम करने के लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद को सार्वभौमिक बनाया। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने जीईएम (जेम) आधारित खरीद में अपनी उल्लेखनीय प्रगति के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
15. सरकार ने 'आपकी ज़मीन आपकी निगरानी' पोर्टल के माध्यम से भूमि प्रशासन में पारदर्शिता की शुरुआत की, जो भूमि अभिलेखों की ऑनलाइन उपलब्धता को सक्षम बनाता है। नागरिक सुविधा और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए भूमि राजस्व दस्तावेजों का पंजीकरण ऑनलाइन किया गया था। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने विकास कार्यों के बारे में पारदर्शिता के लिए सशक्तिकरण/जनभागीदारी पोर्टल भी पेश किया। पोर्टल नागरिकों को सभी चल रहे कार्यों को ऑनलाइन देखने में सक्षम बनाता है और कार्य निष्पादन संबंधी जवाबदेही में सुधार करता है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है और साथ ही प्रूफ (ऑन-साइट सुविधा का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड) प्लेटफॉर्म के माध्यम से जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ कार्य प्रगति की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी शुरू कर दी है।
16. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण** - सभी व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं को परिपूर्ण करने और लाभार्थियों के लिए 100% आधार सीडिंग सुनिश्चित करने के संघ राज्य क्षेत्र के प्रयासों ने उनके खातों में धन का प्रत्यक्ष अंतरण सक्षम किया है। मार्च, 2024 तक 50 से अधिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) आधारित कल्याणकारी योजनाओं (नकद और वस्तुगत दोनों) के माध्यम से 70.46 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6000 करोड़ रुपये से अधिक का निर्बाध वितरण किया गया। जम्मू और कश्मीर ने 2023-24 में 74 करोड़ 42 लाख ई-लेनदेन दर्ज किए, जो प्रतिदिन पंजीकृत 20 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन का औसत है, जो कई राज्यों की तुलना में अधिक है।

17. विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का डेटाबेस हटाने के लिए आधार सीडिंग का कार्य व्यवस्थित रूप से शुरू किया गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन और ई-पीओएस मशीनों के प्रावधान से राशन आपूर्ति के तहत डीबीटी और आधार आधारित सत्यापन के माध्यम से लगभग 230 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसी तरह, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत डीबीटी का लाभ उठाकर 200 करोड़ रुपये से अधिक की बचत सुनिश्चित की गई है।

### **आर्थिक और औद्योगिक क्षमता का दोहन करना**

18. **कृषि और संबद्ध क्षेत्र** - कृषि और संबद्ध क्षेत्र को आजीविका के स्थायी स्रोतों के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए, किसानों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी पहल की गई है, जिससे उनकी आय में सुधार हुआ है। सरकार पूरे वर्ष स्थायी आय सुनिश्चित करने के लिए सभी कृषि भूमि को दोफसल पैटर्न के तहत लाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने उच्च घनत्व वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर भूमि उपयोग में दक्षता में सुधार के लिए काम किया है। सेब उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए मध्यम घनत्व के तहत 17,390 हेक्टेयर और उच्च घनत्व वाले फल रोपण के तहत 663 हेक्टेयर शामिल किया गया है। ताजे फलों और मेवों का उत्पादन 2018-19 में 20.06 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 26.43 लाख मीट्रिक टन हो गया जिससे इन वर्षों के दौरान लगभग 10% की बढ़त दर्ज हुई।
19. नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण क्षमता को 2018 में 1.14 एलएमटी से बढ़ाकर 2024 में 2.70 एलएमटी कर दिया गया है। 2023-24 के दौरान 60,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले बारह (12) सीए स्टोर पूरे हो चुके हैं और 2024 -25 के दौरान 25,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले सात (7) नए सीए स्टोर शामिल किए जाएंगे। किसान परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अब तक कुल 10.90 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरित किए गए हैं। कुल 17 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के साथ एकीकृत किया गया है और 98 एफपीओ सहित 51,748 किसानों और व्यापारियों को पंजीकृत किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12.68 लाख पात्र किसानों के बैंक खातों में 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशियां सीधे जमा करवायी जा चुकी हैं।

20. संघ राज्य क्षेत्र सरकार गुणवत्ता वाले बीज, कृषि मशीनीकरण, उच्च घनत्व वृक्षारोपण, कोल्ड स्टोरेज और किसान बीमा में निवेश करके कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित कर रही है। इसके लिए, सरकार ने 5,013 करोड़ रुपये के पर्याप्त आवंटन के साथ "समग्र कृषि विकास कार्यक्रम" के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 29 पहलें कीं। इस कार्यक्रम से इन क्षेत्रों से मूल्य संवर्धन को दोगुना करने, क्षेत्रीय विकास दर को 11% तक बढ़ाने, 2.88 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और अगले पांच वर्षों के भीतर लगभग 19,000 उद्यम स्थापित करने की उम्मीद है।
21. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ने और किसानों और सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रदान किए गए ऋण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, 537 पीएसीएस को पुनरुद्धार के लिए प्राथमिकता दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पंचायत में एक अनुमोदित पीएसीएस हो ताकि यह समावेशी रूप से संचालित हो और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायता मिले। कारीगरों और बुनकरों को 5 वर्षों की अवधि के लिए 7% की आकर्षक ब्याज सहायता के साथ क्रेडिट कार्ड योजना प्रदान की जा रही है।
22. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3.40 लाख घरों को मंजूरी दी गई है और 2.10 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। 477 भूमिहीन परिवारों को गृह निर्माण के लिए 5 मरला भूमि आवंटित की गई। मनरेगा के तहत वार्षिक कार्यों की संख्या भी वर्ष 2019-20 में 54,300 से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक 1,24,623 तक हो गई।
23. **पर्यटन-पर्यटन** जम्मू और कश्मीर के लिए जीवन रेखा है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदान देता है। धरती के इस स्वर्ग में वर्ष 2023 के दौरान 2.11 करोड़ पर्यटकों का रिकॉर्ड आवागमन देखा गया है। वर्ष 2024 में जून, 2024 तक लगभग 1.02 करोड़ पर्यटक पहले ही आ चुके हैं। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के अलावा, शिवखोरी, मानसर-सुरिनसर, पटनीटॉप, दूधपथरी और लोलाब जैसे ऑफबीट स्थलों में पर्यटकों का बहुत अधिक आवागमन है। गुरेज और सुचेतगढ़ जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन के पुनरुद्धार से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।



24. पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के बाद, इस क्षेत्र में निवेश में भारी वृद्धि देखी गई है। पर्यटन विभाग ने पर्यटन के इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं में सुधार और पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ावा देने में निवेश किया है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए, संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने होम स्टे नीति आरंभ की। जम्मू और कश्मीर में अब तक 14,180 बिस्तर की क्षमता वाले 1,942 होम स्टे पंजीकृत किए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र फिर से दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण के रूप में उभर रहा है, जो जम्मू और कश्मीर को एक प्रमुख फिल्म निर्माण स्थल के रूप में स्थापित कर रहा है। वर्ष 2023 में जम्मू और कश्मीर में 102 फिल्मों/वेब सीरीज की शूटिंग की गई है।
25. **औद्योगिक विकास** - सरकार नए निवेश को आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों का विस्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमने इस दिशा में जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30, औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30, जम्मू-कश्मीर स्टार्ट-अप नीति 2024-27, निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति 2021-30, ऊन प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा नीति 2020 शुरू की है।
26. केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021 से केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना (एनसीएसएस) शुरू की है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार की सक्रिय नीतियों के साथ-साथ एनसीएसएस लाभों से वर्ष 2023-24 के दौरान 3,389 करोड़ रुपये की निवेश प्राप्ति सुनिश्चित की गई है। 18,185 करोड़ रुपये के निवेश और 46,857 रोजगार के साथ कुल 889 इकाइयों ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। 9,538 करोड़ रुपये के निवेश के साथ इन 889 इकाइयों में से 324 इकाइयों के वर्ष 2024-25 के दौरान उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है।
27. मौजूदा 64 औद्योगिक संपदाओं के अलावा, 'मेड इन जम्मू और कश्मीर' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 46 संपदाएं विकसित की जा रही हैं। शिल्प उद्योग को बढ़ावा देने

के लिए कारखंडर योजना कार्यान्वित की जा रही है। सरकार ने पिछले एक वर्ष में 656 स्टार्ट-अप को मान्यता दी है।

28. वैश्विक हस्तशिल्प मानचित्र पर जम्मू-कश्मीर के उत्पादों को नई पहचान दिलाने के लिए 10 क्राफ्ट्स हेतु जीआई टैगिंग को मंजूरी दी गई है और 12 अन्य उत्पादों के जीआई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। एक प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी ने एक मजबूत वेब पोर्टल विकसित किया है जो जम्मू-कश्मीर के हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराएगा। वर्ष 2021-22 में हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात 563 करोड़ रुपये से दोगुना होकर वर्ष 2023-24 में 1,162 करोड़ रुपये हो गया है।

### जीवन की गुणवत्ता में सुधार

29. **स्वास्थ्य देखभाल** - स्वास्थ्य क्षेत्र के अवसंरचनात्मक उन्नयन के परिणामस्वरूप जन स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। दो एम्स और दो कैंसर संस्थानों सहित 4,000 से अधिक के निर्माण से स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के साथ, जम्मू और कश्मीर ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
30. 9 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। एमबीबीएस की सीटें 500 से बढ़कर 1,300 हो गई हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 26 बी.एस.सी नर्सिंग कॉलेज और 19 बीएससी पैरामेडिक कॉलेज जोड़े गए हैं।
31. सेहत पहल के माध्यम से, सभी निवासियों को प्रति परिवार 5 लाख रुपये का सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा मुफ्त प्रदान किया गया है। 85.49 लाख से अधिक व्यक्तियों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं और लगभग 251 अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए **एबी-पीएमजेवाई-सेहत** योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अब तक 2,285 करोड़ रुपये की लगातार से लगभग 12.90 लाख लोगों को उपचार की सुविधा प्रदान की जा चुकी है, जिससे जिससे अगस्त 2020 तक 3.60 लाख लाभार्थियों को सुविधायें प्रदान की जा चुकी हैं। यह योजना बड़े स्तर पर जनता के लिए एक गेम चेंजर के रूप में है जैसा कि इससे एक

स्वस्थ जीवन जीने के लिए उपचार हेतु जरूरतमंद लोगों को समय पर उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

32. संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने वर्ष 2019 से 3104 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू किए हैं। जन औषधि केंद्रों का विस्तार वर्ष 2019 में 38 से बढ़ाकर मार्च 2024 तक 270 कर दिया गया है। आपातकालीन देखभाल के लिए 489 से अधिक नई एम्बुलेंस तैयार की गई हैं। इन उपायों ने संघ राज्य क्षेत्र के आईएमआर को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 के अनुसार 22.0 से घटाकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 16.3 करने और जन्म के समय लिंगानुपात को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 के अनुसार 927 से बढ़ाकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार 976 करने में भी मदद की है।
33. **शिक्षा** -वर्ष 2019 के बाद से संघ राज्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण से प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2019-20 में 12.40 लाख से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 14.18 लाख से अधिक हो गया है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने 15,000 पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का कार्य शुरू करके बचपन से शिक्षा प्रदान करने की पहल शुरू की है।
34. प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना के तहत, पहले और दूसरे चरण में 389 स्कूलों के स्तरोन्नयन के लिए मंजूरी दी गई है। लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। सार्वभौमिक शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए स्कूल न जाने वाले 46,000 बच्चों की पहचान की गई है, उन्हें विभिन्न स्कूलों में नामांकित किया गया है और उन्हें मुख्यधारा में लाया गया है। सभी स्कूलों में चेहरे की पहचान आधारित उपस्थिति प्रणाली स्थापित करके शिक्षण कर्मचारियों की समय की पाबंदी और कार्य अनुशासन को बढ़ाया गया था। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की क्षमता में 600 अतिरिक्त सीटों के साथ वृद्धि की जा रही है।
35. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रारंभ किया गया है और सभी कॉलेजों में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 2019 से 51 नए डिग्री कॉलेज स्थापित होने के साथ उच्च शिक्षा में तेजी आई है। ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा हेतु, 50 विषयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामग्री विकसित और अपलोड की गई है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने शिक्षकों और संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए

यूनिक फीडबैक पोर्टल की स्थापना की है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के वित्त पोषण के तहत परियोजनाओं के माध्यम से कॉलेज और विश्वविद्यालय की अवसंरचना को अधिक बढ़ावा मिला है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों को भूमि और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके प्रारंभ किया गया था।

36. **खेल-कूद** - तीन दशकों के बाद, जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट शुरू हुए हैं, जिसका उद्देश्य देश में एक प्रमुख क्रीडा स्थल के रूप में खुद को स्थापित करना है। वर्ष 2019 में किए गए सुधारों से पूरे संघ राज्य क्षेत्र में 702 खेल परियोजनाओं को पूरा करने, 100 खेलो इंडिया केंद्रों के निर्माण और इनडोर खेल परिसरों के विकास के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में खेल क्षेत्र और युवाओं की प्रतिभागिता में क्रांति की शुरुआत हुई है। लगभग हर जिले में बहुउद्देशीय इनडोर स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण किया गया है। प्रत्येक पंचायत में खेल के मैदान विकसित किए गए हैं। कई स्टेडियमों में फ्लडलाइटिंग और सिंथेटिक टर्फिंग लगाई जा रही है।
37. जम्मू-कश्मीर दोनों डिवीजनों में कैनोइंग, रोइंग और फेंसिंग में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। सिंथेटिक हॉकी टर्फ, केके हक्कू स्टेडियम, जम्मू और सिंथेटिक हॉकी टर्फ, पोलोग्राउंड, श्रीनगर का निर्माण किया गया था और भारतीय हॉकी परिसंघ (एफआईएच) द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था। खेलगांव, नगरोटा में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ विकसित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर देश के शीतकालीन खेल की राजधानी के रूप में उभर रहा है। मार्च 2020 से खेलों इंडिया के शीतकालीन खेलों की 04 प्रतियोगिताओं का आयोजन गुलमर्ग - संसार का प्रसिद्ध शीतकालीन स्थल में किया गया है।
38. **रोजगार** - सरकार ने आजीविका सृजन, शिक्षा और कौशल विकास, परामर्श, खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में सुव्यवस्थित पहलों के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के युवाओं को शांति और विकास के राजदूत में बदलने के लिए एक अग्रणी पहल-मिशन यूथ की परिकल्पना की थी। मुमकिन, तेजस्विनी और स्परिंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम की मिशन यूथ पहल के तहत बड़ी संख्या में युवाओं और महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

39. हमने बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान भी शुरू किया। अगस्त 2019 से सरकारी क्षेत्र में निष्पक्ष, योग्यता आधारित, पारदर्शी और त्वरित तरीके से कुल 38,384 व्यक्तियों की भर्ती की गई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर **34 लाख से अधिक श्रमिकों** का पंजीकरण किया गया है। वर्ष 2021-22 से अब तक कुल 7.66 लाख स्वरोजगार/आजीविका के अवसर पैदा/मजबूत हुए हैं।

## सामाजिक और वित्तीय समावेशन का विस्तार

40. जनजातीय समुदाय से जनजातियों की नई पीढ़ी के छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, 25 छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। आजीविका इकाइयां, कौशल विकास और पेशेवर कोचिंग जैसी पहल आदिवासी युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रही हैं। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण के लिए महत्वपूर्ण पहल की हैं। प्रवासी जनजाति समुदायों को पारगमन सुविधाएं प्रदान की गईं। 8 नए छात्रावास भवन, 285 स्मार्ट स्कूल, 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय विकसित किए गए हैं। विभाग ने समर्पित कोचिंग सुविधाएं, 2,000 आदिवासी युवाओं को कौशल विकास और 46,000 जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है। दो दशकों के लंबे इंतजार के बाद, आदिवासी समुदायों को वन्य अधिकार दिए गए।
41. संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने विधवाओं, वृद्धों और दिव्यांगजनों के लिए अपने सामाजिक सुरक्षा कवर का विस्तार किया है। मासिक सहायता/पेंशन लाभ वर्ष 2014-15 में लगभग 5.0 लाख लाभार्थियों से बढ़ाकर वर्ष 2023-24 में लगभग 8.61 लाख कर दिया गया। मेरिट-कम-मीन्स अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत, सरकार ने वर्ष **2023-24** में 15,957 छात्रों को शामिल किया गया है। इसी तरह से वर्ष 2023-24 के दौरान अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 9,879 छात्रों को शामिल किया गया है।
42. संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने 3000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवों में ईट और मोर्टार शाखाएं स्थापित करने को प्राथमिकता दी है। स्थायी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिकता प्रदत्त 10 गांवों में से 9 गांवों को कवर कर लिया गया है। 167 गांव जिनके पास 5 किमी के दायरे में बैंकिंग सेवाएं

नहीं थीं, अब बैंकिंग संपर्क सूत्रों या स्थायी शाखाओं के माध्यम से कवर किए गए हैं।

43. पीएम-स्वनिधि योजना के तहत, 26,596 स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी के साथ विशेष ऋण सुविधा प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत, सभी बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 3,63,817 लाभार्थियों को 8,063.19 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। 31 मार्च, 2024 तक बैंकों द्वारा 8.83 लाख केसीसी (फसल) खाताधारकों को 7,686 करोड़ रुपये के रियायती ऋण को मंजूरी दी गई है। 2 लाख केसीसी-एचएफ (पशुपालन और मत्स्य पालन) लाभार्थियों को 1,559 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
44. **महिला सशक्तिकरण** - सरकार ने "लाडली बेटी" की कवरेज को 2017 में 16,095 मामलों से बढ़ाकर 2023-24 तक 1,61,552 मामलों तक बढ़ा दिया है। इस अवधि के दौरान पात्र बालिकाओं के लिए वित्तीय सहायता को 24 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 847 करोड़ रुपये कर दिया गया है। विवाह सहायता योजना के तहत 2015-16 से 2023-24 तक 1,04,326 गरीब लड़कियों को 394 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
45. सात लाख से अधिक महिलाएं लगभग 90,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। लगभग तीन लाख महिला किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। महिला किसानों ने अपने परिवारों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग दो लाख कृषि पोषण उद्यान स्थापित किए हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन अब संघ राज्य क्षेत्र में 'लखपति दीदी' को बढ़ावा देने और नए माइक्रो-स्टार्टअप स्थापित करने के लिए काम कर रहा है।
46. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत अब जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से एक तिहाई सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है।

## अवसंरचना के विकास में तेजी लाना

47. केंद्र सरकार के समर्थन से, संघ राज्य क्षेत्र ने अवसंरचना के विकास में तेजी लाने के लिए पूंजीगत निवेश बढ़ाया है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत, 53 परियोजनाओं के लिए 49,975 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जिनमें से मई, 2024 तक 48,359 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है और 35 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या पूरा होने वाली हैं।
48. 3,268 करोड़ रुपये की लागत की 1,646 अवरूद्ध परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई और त्वरित वित्त पोषण के माध्यम से इन्हें पूरा किया गया है।
49. **विद्युत क्षेत्र** - संघ राज्य क्षेत्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक अपनी स्थापित जल विद्युत क्षमता को 3500 मेगावाट से बढ़ाकर लगभग 6500 मेगावाट करना है। इसके लिए, इसने 624 मेगावाट क्षमता वाली कीरू, 850 मेगावाट क्षमता वाली रातले, 1000 मेगावाट क्षमता वाली पाकल दुल और 540 मेगावाट क्षमता वाली क्वार परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एनएचपीसी के साथ साझेदारी की है। केंद्र सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र के इक्विटी योगदान के लिए 2430.60 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।
50. हम 3284 मेगावाट क्षमता की 04 और पनबिजली परियोजनाओं के विकास पर भी काम कर रहे हैं, जिनके नाम हैं सावलकोट (1856 मेगावाट), दुल हस्ती चरण-II (258 मेगावाट), उरी-I चरण-II (240 मेगावाट), और किरथाई-II (930 मेगावाट), जिसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है। संघ राज्य क्षेत्र को निःशुल्क विद्युत के अपने हिस्से, स्थिर विद्युत की दीर्घकालिक आपूर्ति, आर्थिक कार्यकलापों के विस्तार और रोजगार के अवसरों के सृजन से भी लाभ होगा। सरकार छोटी पनबिजली परियोजनाओं और रूफ-टॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास पर भी जोर दे रही है।
51. वर्ष 2019-24 के दौरान पारेषण क्षमता में लगभग 50% की भारी वृद्धि ने दूरदराज के गांवों में विद्युत आपूर्ति के विस्तार को सक्षम किया है। उत्तरी कश्मीर में गुरेज घाटी को विद्युत ग्रिड से जोड़ा गया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया मिशन मोड

में चल रही है। जून 2024 तक 5.74 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के साथ मीटर वाले क्षेत्रों में 15% की हानि को कम करने में सफलता प्राप्त हुई है।

52. **फिजिकल कनेक्टिविटी-** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के वित्तपोषण का लाभ उठाकर, संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने बस्तियों तक तेजी से सड़क नेटवर्क का विस्तार किया। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर विचार करते हुए, 250+ आबादी वाली सभी ग्रामीण बस्तियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ा गया है, और वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शेष गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है।
53. पिछले चार वर्षों में पीएमजीएसवाई के तहत विभिन्न गांवों में 7,886 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। कड़ी निगरानी और त्वरित क्रियान्वयन के माध्यम से सड़क निर्माण की गति दोगुनी हो गई है। वर्ष 2017-20 के दौरान 2,914 परियोजनाएं पूरी की गईं और 9,382 किलोमीटर सड़कों पर तारकोल बिछाया गया, जबकि वर्ष 2020-24 के दौरान 9,235 से अधिक परियोजनाएं पूरी हुईं और 21,799 किलोमीटर सड़कों पर तारकोल बिछाया गया। इससे दूरदराज के गांवों तक सड़क संपर्क में काफी सुधार हुआ है और इस हिमालयी संघ राज्य क्षेत्र में यात्रा का समय काफी कम हुआ है।
54. जम्मू (58 किलोमीटर) के लिए सेमी-रिंग रोड का काम पूरा होने वाला है, जबकि श्रीनगर के लिए सेमी-रिंग रोड को चार लेन करने के काम में 48% की वास्तविक प्रगति हुई है। पट्टन और बारामुल्ला शहरों के लिए बाईपास के साथ श्रीनगर-बारामुल्ला-उरी मार्ग के उन्नयन का काम 3,554 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया है। 8.45 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब काजीगुंड-बनिहाल सुरंग के निर्माण से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगने वाले समय की काफी बचत हुई है। श्रीनगर-लेह मार्ग पर 13.15 किलोमीटर 2-लेन वाली बाई-डायरेक्शनल जोजिला सुरंग और 6.40 किलोमीटर जड-मोड़ सुरंग पर क्रमशः 4,509 करोड़ रुपये और 2,379 करोड़ रुपये की लागत से काम अंतिम चरण में है। एनएच-244 पर सुखमहादेव-द्रंगा सुरंग। और II (8 किमी) के लिए 3,703 करोड़ रुपये की लागत से ईपीसी मोड में परियोजना के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। एनएच 244 पर 1.574



किलोमीटर खेलानी बाईपास सुरंग पर चल रहे कार्य में 67% की वास्तविक प्रगति हुई है, जबकि एनएच 244 की चमोटी से द्राबशाला तक 495 मीटर सुरंग पर 50% कार्य पूरा हो गया है।

55. **रेल कनेक्टिविटी-** जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे पर काम कमीशनिंग के अंतिम चरण में है। बनिहाल-खारी-सुम्बर-संगलदान खंड (48 किमी) और रियासी-संगलदान खंड (46 किमी) के बीच रेलवे लाइन और बारामुल्ला-श्रीनगर-बनिहाल-संगलदान खंड (186 किमी) का विद्युतीकरण वर्ष 2023-24 के दौरान पूरा हो चुका है। इसके साथ ही, सामाजिक-आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस रेलवे लाइन (272 किमी) में से 255 किमी रेलवे लाइन चालू कर दी जाएगी। कटरा-रियासी (17 किमी) से शेष खंड का कार्य 2024-25 में पूरा होने की संभावना है।
56. **सिंचाई और जलापूर्ति** - जम्मू की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के लिए 1.41 एमसीएम जलसंग्रह क्षमता वाली कृत्रिम झील बनाने की परिकल्पना के साथ तवी बैराज परियोजना पर काम पुनः प्रारंभ हो गया है। परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है और इस वित्तीय वर्ष के दौरान यह कार्य 64.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा हो जाएगा।
57. शाहपुर कंडी बांध परियोजना पर कार्य तेजी से हो रहा है और इससे जम्मू-कश्मीर को रावी नदी से 1,150 क्यूसेक पानी का अपना हिस्सा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
58. जल जीवन मिशन के तहत, जम्मू और कश्मीर ने 13,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 3,256 योजनाओं की परियोजना बनाई है। 18.69 लाख ग्रामीण घरों में से, 15.08 लाख (80.64%) ग्रामीण घरों को काम करने वाले नल कनेक्शन प्रदान किए हैं। संघ राज्य क्षेत्र में दो जिलों-श्रीनगर और गांदरबल में 100% घरेलू नल के कनेक्शन परिपूर्ण प्रदान किए हैं।
59. झेलम नदी और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (चरण-I) को 31,800 क्यूसेक से 41,000 क्यूसेक तक बढ़ाने के लिए चालू किया गया। इस परियोजना का चरण-II 1,623 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से शुरू हो गया है।

होकरसर वेटलैंड के प्रवेश और निकास द्वार के निर्माण का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा।

60. **शहरी विकास एवं आवासन** - स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दोनों स्मार्ट शहरों में शहरी अवसंरचना के पुनरुद्धार के लिए 309 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें पीपीपी मोड पर 666 करोड़ रुपये की लागत वाली 20 परियोजनाएं और कन्वर्जेंस मोड पर 3,475 करोड़ रुपये की लागत वाली 55 परियोजनाएं शामिल हैं। श्रीनगर स्क्वायर, लाल चौक, झेलम रिवर फ्रंट का विकास/उन्नयन, पोलो व्यू हाई स्ट्रीट का पुनर्विकास, पारंपरिक सोक बाजार, शिल्प केंद्र बटमालू, उत्तरी फोरशोर रोड, निशात से नसीम बाग हबक तक लेकफ्रंट, डोगरा चौक से केसी चौक तक सड़क का सुधार, अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट, कैनाल रोड का विकास, मुबारक मंडी से रघुनाथ बाजार तक तालाब तिल्लो स्ट्रीट का विकास आदि परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
61. हरित शहरी परिवहन पहल के अंतर्गत स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 200 ई-बसें शुरू की गई हैं और ये विनिर्दिष्ट बसें इंटर/इंट्रासिटी मार्गों पर चल रही हैं। इसके अलावा, पीएम ई-बस सेवा के तहत स्वीकृत 200 और ई-बसें निकट भविष्य में शुरू की जाएंगी। साथ ही, दोनों राजधानी शहरों में पर्यावरण अनुकूल ई-रिक्शा/ई-ऑटो, सार्वजनिक साइकिलें शुरू की गई हैं।
62. ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों के लिए बीरपुर (सांबा), पदगमपुरा (पुलवामा), छतरहामा (गांदरबल) बलवाल, रूप नगर और चौवाड़ी जम्मू में आवासीय कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। इसके अलावा, वाटापोरा (बांदीपोर) में एकीकृत जन आवास कॉलोनी और रख-गुंड अक्षा में सैटेलाइट टाउनशिप भी विकसित की जा रही है। इसके अलावा, अमृत निधि के तहत, 82 परियोजनाएं पूरी की गईं, जिनमें 13,000 सीवरेज कनेक्शनों के साथ 74 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाना, 1,596 वाहनों के लिए पार्किंग स्थलों का विकास, 6 किलोमीटर पैदल यात्री मार्ग का निर्माण, 104 किलोमीटर बारिश के पानी की नालियों का निर्माण और 46,165 वर्ग मीटर हरित स्थानों का विकास शामिल है। 3 लाख लोगों हेतु जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रंगील में 30 एमजीडी क्षमता वाले जल उपचार संयंत्र तक 1200 मिमी व्यास की 3 किलोमीटर लंबी जलापूर्ति लाइन बिछाई गई।

## शासन का विकेंद्रीकरण और जन-सम्पर्क को मजबूत करना

63. जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में वर्ष 2020 के संशोधन के बाद संविधान में 73वें संशोधन को पूरी तरह से अपनाया गया। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सशक्त बनाया गया और विकेंद्रीकृत योजना, निर्णय लेने और पर्यवेक्षण के लिए इन संस्थाओं को सत्ताईस विषयों को अंतरित किया गया।
64. वर्ष 2019 में पीआरआई के विभिन्न स्तरों के लिए चुनाव हुए जिससे वित्त आयोग के अनुदान जारी करने में आसानी हुई। तब से ग्राम पंचायत आधारित विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) भागीदारी नियोजन के माध्यम से तैयार की गई हैं और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रियान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति देने की शक्ति पंचायत स्तर पर पीआरआई को सौंपी गई है।
65. हम स्थानीय सरकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में, संघ राज्य क्षेत्र सरकार स्थानीय निकाय चुनाव कराने की तैयारी कर रही है, जिसमें आरक्षण प्रदान करने के लिए संवैधानिक दायित्वों के लिए चुनाव भी शामिल हैं।
66. पुनर्गठन के बाद, जम्मू-कश्मीर ने जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचने और उनकी जरूरतों को समझने के लिए महत्वाकांक्षी बैक टू विलेज (B2V) कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक, इस B2V कार्यक्रम के पांच दौर आयोजित किए गए हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी गांवों का दौरा किया। यह पहल काफी लोकप्रिय हो गई है क्योंकि इस तरह के दौरे और स्थानीय बातचीत से आम लोगों की शिकायतों का निवारण करने में मदद मिली है।
67. बैक टू विलेज (B2V) कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में, लोगों को घर तक कल्याणकारी कार्यक्रम की पहुंच के लिए “जन-अभियान”, “जन दरबार” और “ब्लॉक दिवस” आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सबसे पिछड़े ब्लॉकों और पंचायतों के विकास संबंधी अंतराल को समाप्त करने के लिए “आकांक्षी ब्लॉक विकास” और “आकांक्षी पंचायत विकास” कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

## सामाजिक न्याय के लिए कानूनी सुधार

68. संविधान के सभी प्रावधान और महत्वपूर्ण केंद्रीय विधायनों जैसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (वन्य अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1954, सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रीय विधायनों का लाभ अब जम्मू और कश्मीर के लोगों को मिल रहा है।
69. इन सुधारों ने विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए समाज के अब तक वंचित वर्गों जैसे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों, सफाई कर्मचारियों और वाल्मीकि जो दशकों से जम्मू और कश्मीर में रह रहे थे को मतदान का अधिकार प्रदान करके सक्षम भी बनाया है। इसके अलावा, इन सुधारों ने पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों, सफाई कर्मचारियों और वाल्मीकियों, जम्मू और कश्मीर के बाहर विवाहित स्थानीय महिलाओं के बच्चों और इसी तरह की स्थिति वाले अन्य लोगों को निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद की, जिससे उनका अभाव और भेदभाव समाप्त हो गया।
70. जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए आरक्षण देने और साथ ही जम्मू और कश्मीर की “अन्य पिछड़ी जातियों” को देश के अन्य हिस्सों के समान लाने के लिए संशोधन किया गया।
71. सकारात्मक कार्रवाई के हिस्से के रूप में, उनके उत्थान के लिए पहाड़ी भाषी लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया गया है। पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करके पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों से कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापितों को नामांकन के माध्यम से विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

72. हमने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से जम्मू-कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी निर्वाचित सीटों में से एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का भी प्रावधान किया है।

### **ई-गवर्नेंस पहल**

73. संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से डिजिटल शासन की ओर बदलाव की शुरुआत की है। जिला स्तर तक के 450 से अधिक सरकारी कार्यालय फिजिकल फाइलों से ई-फाइलिंग प्रणाली में स्थानांतरित हो गए हैं। इसे अपनाने से सरकार को दरबार मूव को समाप्त करने और सालाना भारी व्यय बचाने में सहायता मिली।
74. संघ राज्य क्षेत्र ने 1100 से अधिक नागरिक केंद्रित सेवाओं को ऑनलाइन प्रदायगी करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की और इस प्रकार एनईएसडीए (राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन) रैंकिंग में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की। इस डिजिटल क्रांति ने शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया है।

### **वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था की स्थिति**

75. जम्मू और कश्मीर सबसे तेजी से बढ़ते संघ राज्य क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व संग्रह में हुई वृद्धि से इसकी पुष्टि होती है। माल और सेवा कर के तहत राजस्व संग्रह वर्ष 2023-24 में 8,064 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो वर्ष 2022-23 में इस राजस्व से 12 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2022-23 में मोटर स्पिरिट करों से 1,554 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति की तुलना में वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति की राशि 1,631 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2022-23 के दौरान स्टॉप और पंजीकरण राजस्व 557 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2023-24 में 678 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है, जो 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान उत्पाद शुल्क संग्रह 1,794 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2023-24 में 2490 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष (वर्ष 2023-24) के

लिए जीडीपी वृद्धि 7.5% रहने की संभावना के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत है।

76. संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने सभी क्षेत्रों में समान विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण नीतियों का पालन किया है। विकासात्मक पहलों को बनाए रखने के लिए, केंद्रित प्रवर्तन और डीलर आउटरीच अभियान चलाए गए। सरकार ने विवेकपूर्ण ढंग से कर और गैर-कर संबंधी उपाय किए।
77. वर्ष 2018-19 में जीएसटी के तहत डीलर पंजीकरण को लगभग 72,000 से बढ़ाकर वर्ष 2023-24 में 2,00,000 से अधिक कर दिया गया है। सनदी लेखाकार संस्थान के सहयोग से कराधान कर्मचारियों की क्षमता निर्माण का कार्य किया गया। जीएसटी लीकेज को रोकने के लिए, खरीद को ट्रैक करने के लिए तंत्र विकसित किया गया। पूंजीगत कार्यों के तहत जीएसटी कटौती को ट्रैक करने और कर वसूली में सुधार के लिए, जीएसटीएन सत्यापन को बिल भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है।
78. संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने नई आबकारी नीति को अधिसूचित किया और शराब की दुकानों के आवंटन में नीलामी की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से सभी सुनियोजित दुकानें स्थापित कीं। एनआईसी के सहयोग से, संघ राज्य क्षेत्र ने दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए ई-स्टाम्पिंग प्रणाली शुरू की। इससे स्टाम्प और पंजीकरण राजस्व वर्ष 2018-19 में 190 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 678 करोड़ रुपये हो गया। आपूर्ति श्रृंखला पर निगरानी रखने और उत्पाद शुल्क राजस्व बढ़ाने के लिए ई-आबगारी प्लेटफॉर्म को सुदृढ़ किया जा रहा है। इन उपायों की वजह से जीएसटी, उत्पाद शुल्क और स्टॉप से मिलने वाले राजस्व में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है।
79. गैर-कर संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि और रेजीलिएंस दिखी है। विद्युत की खपत पर निगरानी हेतु एरियल बंचिंग केबल और स्मार्ट मीटर लगाने पर विशेष ध्यान दिया गया। लगभग 5.74 लाख स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं के व्यवहार में परिवर्तन आया है और विद्युत की खपत सीमित हुई है और वर्ष 2023-24 में टैरिफ राजस्व में भी लगभग 10% की वृद्धि हुई है।

80. वर्ष 2019 के बाद कई प्रयासों के माध्यम से इस सुदृढ़ आधारशीला के साथ, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर अब अपने विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए तैयार है। इस वार्षिक बजट में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे दिए गए हैं

## 81. आर्थिक क्षेत्र

### 81.1 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र:

- i. कृषक समुदाय को घर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2000 किसान खिदमत घर (केकेजी) की स्थापना। बीज प्रणालियों को सुदृढ़ करके, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देकर, कृषि-व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर और बढ़ी हुई रोजगारों और आय सृजन के माध्यम से आजीविका को सुरक्षित करके समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना।
- ii. विभागीय बीज गुणन फार्मों को सुदृढ़ करना।
- iii. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के ऋण के साथ जम्मू और कश्मीर में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार परियोजना (जेकेसीआईपी) को क्रियान्वित किया जाएगा। परियोजना का लक्ष्य कृषि के संचालन की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके ग्रामीण परिवारों की आय में निरंतर वृद्धि में योगदान देना है।
- iv. समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत अनुमोदित सभी 29 परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
- v. 20 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उत्पादों की पहचान की गई है, जिनमें से 05 उत्पादों (केसर, सुलई शहद, मुश्कबुदगी चावल, भद्रवाह राजमाश और उधमपुर कलारी) को भौगोलिक संकेतक (जीआई) पंजीकरण मिल चुका है और शेष प्रक्रियाधीन हैं।
- vi. कृषि मशीनरी का वितरण जिससे 70,000 किसान लाभान्वित होंगे।
- vii. उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और बागों के कायाकल्प के लिए डिजाइनर पौधों का उत्पादन।

- viii. 25,000 मीट्रिक टन कंट्रोलड एटमस्फीयर (सीए) भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी।
- ix. श्रीनगर के चश्मोशाही में गुलदाउदी थीम पार्क का विकास।
- x. 3,000 डेयरी इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिससे लगभग 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
- xi. पांच वर्षों की अवधि में दूध उत्पादन में 25 से 45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि तथा दूध संग्रहण/चिलिंग में 2.0 से 8.5 लाख लीटर प्रतिदिन (एलएलपीडी) की वृद्धि।
- xii. निजी क्षेत्र में 100 सैटेलाइट बछिया पालन इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- xiii. 1,800 पशु सखियों को 6,00,000 गायों के लिए राशन बैलेंसिंग तथा 30,000 डेयरी गायों के दूध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।
- xiv. ग्रामीण क्षेत्रों में 60,000 बैकयार्ड पोल्ट्री इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- xv. 3,600 हेक्टेयर भूमि के लिए हाइब्रिड चारा बीज किट उपलब्ध कराई जाएंगी।
- xvi. चारे की कमी वाले क्षेत्रों में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 100 जलीय चारा इकाइयां तथा 60 साइलिज मेकिंग इकाइयां, साथ ही 6 चारा डिपो स्थापित किए जाएंगे।
- xvii. तकनीकी हस्तक्षेप से मछली उत्पादन को 30,670 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 35,250 मीट्रिक टन किया जाएगा।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों हेतु वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 2053.39 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 524.33 करोड़ रुपये अधिक है।

## 81.2 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राजः

- i. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 400 लाख मानव दिवस सृजित किए जाएंगे।
- ii. हिमायत के तहत लगभग 7000 व्यक्तियों का प्रशिक्षण पूरा किया जाएगा।



- iii. वर्ष 2024-25 के दौरान 12,000 अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए जाएंगे।
- iv. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ 600 नए पंचायत घर बनाए जाएंगे।
- v. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के सदस्यों को 2.60 लाख मानव दिवसों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- vi. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 80,000 घरों का निर्माण किया जाएगा।
- vii. 06 गांवों में ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं होंगी ताकि वे कूड़े और प्लास्टिक से मुक्त होकर स्वच्छ बन सकें।
- viii. वर्ष 2024-25 के दौरान एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत 1800 कार्यों को पूरा करने के साथ 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 हेतु पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 3731.54 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

### 81.3 पर्यटन और संस्कृति:

- i. पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने और स्थानीय व्यापार तथा रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर संभागों में प्रत्येक में 6, 12 ऑफ-बीट पर्यटन स्थलों में अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए नई पहल।
- ii. केरन को सीमावर्ती पर्यटक गांव के रूप में विकसित करना।
- iii. तोसामैदान और सीतारण सर्किट का विकास।
- iv. सांबा में डुग्गर दानी गांव का विकास पारंपरिक व्यवस्था के साथ "मॉक विलेज" के रूप में किया जाएगा।
- v. पटनीटॉप में 130 मीटर (425 फीट) ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण और स्थापना।

- vi. 75 चिन्हित विरासत स्थलों/सांस्कृतिक स्थलों के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार का कार्य पूरा करना।
- vii. 8 सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना और संचालन।
- viii. श्री प्रताप सिंह (एसपीएस) संग्रहालय श्रीनगर का विकास और आधुनिकीकरण।
- ix. श्रीनगर में अत्याधुनिक सूफियाना स्कूल के संचालन सहित संरचित कार्यक्रमों के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में सूफीवाद का प्रचार-प्रसार।
- x. सभी पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण।

पर्यटन और संस्कृति क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 हेतु पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 519.70 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 205.45 करोड़ रुपये अधिक है।

#### 81.4 वानिकी एवं पर्यावरण:

- i. 190 लाख देशी पेड़ लगाना तथा 100 लाख कम लागत वाले हरित हस्तक्षेप, जिनका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, मृदा अपरदन को रोकने तथा जैव विविधता को बढ़ाने के लिए है।
- ii. जम्मू एवं कश्मीर के सभी 78 शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम एक नगर वन, नगर वाटिका अथवा एक इको पार्क होना चाहिए।
- iii. वनों के बाहर वृक्षों की संख्या बढ़ाने तथा आजीविका में सुधार के लिए किसानों के बीच स्थानीय, औषधीय एवं आर्थिक महत्व की प्रजातियों के 10 लाख पौधे वितरित किए जाने चाहिए।
- iv. इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घराना, होकरसर तथा शालबुघ जैसी आर्द्रभूमियों में अवसंरचना विकसित की जानी चाहिए।
- v. जम्मू में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) की स्थापना।
- vi. वन से जल, जल से जीवन, जल शेड प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से एक अभिनव जल संरक्षण तकनीक का कार्यान्वयन, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा आर्द्रभूमियों सहित पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार करना।

- vii. इकोटूरिज्म के माध्यम से स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए वुलर झील का संरक्षण और पुनरुद्धार।
- viii. पंचायत स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की भागीदारी के माध्यम से आजीविका सृजन के अवसरों को बढ़ाना और वन उपज के सतत संग्रह और निपटान के लिए एनआरएलएम के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ उन्हें एकीकृत करना।

वर्ष 2024-25 हेतु वन क्षेत्र के लिए, पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 186.45 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 52 करोड़ रुपये अधिक है।

### 81.5 सहकारी क्षेत्र:

- i. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।
- ii. जिला/गांव/ब्लॉक स्तर पर मिनी सुपर बाजारों का निर्माण/स्थापना।
- iii. "विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण" योजना के तहत अनाज भंडारण सुविधा की कमी वाले 6 जिलों में 6 अनाज भंडारण इकाइयों का निर्माण।

सहकारी क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 हेतु पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 5 करोड़ रुपये अधिक है।

## 82. सामाजिक क्षेत्र

### 82.1 स्वास्थ्य एवं कल्याण:

- i. वर्ष 2024-25 के दौरान जम्मू और श्रीनगर में दो कैंसर संस्थान पूरी तरह संचालित हो जाएंगे।
- ii. डीएनबी सीटों को बढ़ाकर 400 करना, जिससे विशेषज्ञों की उपलब्धता में सुधार होगा।
- iii. 1.35 करोड़ आबादी के लिए आभा आईडी बनाकर स्वास्थ्य रिकॉर्ड को परिपूर्ण किया जाएगा।
- iv. उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए 30+ आयु वर्ग के लोगों की शत-प्रतिशत जांच।

- v. 16 मौजूदा सुविधाओं और 10 नई स्वास्थ्य सुविधाओं में डायलिसिस सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा।
- vi. एम्स, अवंतीपोरा को मार्च, 2025 तक कार्यात्मक बनाया जाएगा।
- vii. हंदवाड़ा में नया नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा।
- viii. शेष सभी जिलों को टीबी मुक्त करना।

वर्ष 2024-25 हेतु पूंजीगत व्यय के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 1674.51 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

## 82.2 शिक्षा क्षेत्र:

- i. सभी 13804 स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए 2176 नए बाल विहार स्थापित किए जाएंगे।
- ii. समग्र शिक्षा अभियान के तहत पुस्तकों की खरीद के लिए प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक के स्कूलों को कवर करने के लिए ₹ 5,000 से ₹ 20,000 तक का पृथक वार्षिक पुस्तकालय अनुदान।
- iii. छात्रों के पोषण संबंधी स्वास्थ्य में सुधार के लिए मिड-डे मील योजना के तहत प्राथमिक स्तर (I से VIII) के लगभग 8.95 लाख छात्रों को केवल पौष्टिक चावल दिया जाएगा।
- iv. प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के तहत 389 स्कूलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा।
- v. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) के तहत 3.50 लाख वयस्कों को साक्षर बनाया जाएगा।
- vi. बीपीएल छात्रों के लिए बेटी अनमोल योजना के तहत ₹ 5000 प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति।
- vii. 18,499 स्कूलों को खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर 16.04 करोड़ रुपये का वित्तीय भार होगा।
- viii. 2,584 स्कूलों को आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराए जाएंगे।
- ix. 43 रोबोटिक लैब और 30 वर्चुअल रियलिटी लैब स्थापित की जानी है।
- x. 100 स्कूलों में विज्ञान केंद्रों की स्थापना।

- xi. नए 554 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी।
- xii. वर्ष 2024-25 के दौरान 05 नव स्थापित कॉलेजों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
- xiii. विभिन्न कॉलेजों में दो छात्रावास ब्लॉक, दो विज्ञान ब्लॉक और छह अतिरिक्त व्याख्यान ब्लॉक पूरे किए जाएंगे।
- xiv. वर्ष 2024-25 में 08 कॉलेजों तक पहुँच बनाई जाएगी और उन्हें मान्यता दी जाएगी।
- xv. जम्मू और कश्मीर में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) ई-समर्थ के माध्यम से 100% प्रवेश।

स्कूल और उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लगभग 1284.47 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो 2023-24 के संशोधित आवंटन से 185.69 करोड़ रुपये अधिक है।

### 82.3 सामाजिक/आदिवासी कल्याण:

- i. सभी दिव्यांग व्यक्तियों को निर्मया स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- ii. मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों (बालकों/बालिकाओं) के लिए 04 वात्सल्य सदन, जम्मू/कश्मीर, प्रत्येक में दो, संचालित किए जाएंगे।
- iii. 653 आंगनवाड़ी केन्द्रों को बाल विद्यालयों के रूप में उन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है।
- iv. 11 शक्ति सदन और 04 सखी निवास की स्थापना की जाएगी।
- v. स्वरोजगार योजना में 1502 इकाइयों की स्थापना के साथ 7,708 महिला लाभार्थियों को लक्षित किया जाएगा।
- vi. 14 पलाश और 13 पारिशा बाल देखभाल संस्थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
- vii. जनजातीय आबादी को 250 लघु प्रकार के ट्रैक्टर और लिंक रोड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

- viii. आदिवासी इलाकों में 80 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जाएगा।
- ix. प्रवासी जनजातीय आबादी को स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
- x. ट्रांस-ह्यूमन जनजातीय आबादी के लिए ट्रांजिट आवास स्थापित किए जाएंगे जिसमें 150-200 परिवारों के लिए आवास, सामुदायिक रसोई, चिकित्सा औषधालय, पशु चिकित्सा औषधालय, सामुदायिक शौचालय और पशुधन यार्ड शामिल हैं।
- xi. 500 अनुसूचित जनजाति आबादी वाले 186 गांवों को "प्रधान मंत्री आदि आदर्श योजना (पीएमएएजीवाई)" योजना के तहत कवर किया जाएगा।
- xii. 10 क्लस्टर जनजातीय मॉडल गांवों को 2024-25 में पूरा किया जाएगा।
- xiii. 10 दुग्ध गांवों को 2024-25 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सामाजिक और जनजातीय कल्याण के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 358.52 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 11.32 करोड़ रुपये अधिक है।

#### 82.4 कश्मीरी प्रवासियों हेतु राहत और पुनर्वास:

- i. वर्ष 2024-25 के दौरान कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों हेतु ट्रांजिट आवास के रूप में 1500 फ्लैटों के निर्माण को पूरा करना।
- ii. कश्मीरी प्रवासियों के लिए पीएम-पैकेज के तहत 6000 पदों में से शेष 276 पदों को 2024-25 में भरा जाना है।

कश्मीरी प्रवासियों हेतु राहत और पुनर्वास के लिये 2024-25 के दौरान राजस्व और पूंजीगत व्यय के तहत 1044.92 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो 2023-24 के संशोधित आवंटन से 134.70 करोड़ रुपए अधिक है।

#### 82.5 खेल और युवा पहलें :

- i. वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत, ब्लॉक, जिला, संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न खेल स्पर्धाओं में 75 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा।

- ii. वर्ष 2024-25 में 20 राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा।
- iii. 200 खेल के मैदान और 100 खेल कोर्ट का निर्माण किया जाएगा।
- iv. मौलाना आजाद स्टेडियम, जम्मू और गिंदुन पार्क राजबाग, श्रीनगर में स्विमिंग पूल का निर्माण पूरा किया जाएगा।

खेल क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 145.19 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो 2023-24 के संशोधित आवंटन से 35.19 करोड़ रुपये अधिक है।

#### 82.6 कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण और रोजगार:

- i. उद्यमों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इकोसिस्टम तंत्र बनाने, स्वरोजगार के लिए 5 लाख से अधिक अवसर पैदा करने और ऋण सहायता के माध्यम से निवेश का विस्तार करने के लिए नई पहल।
- ii. 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
- iii. बड़े व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से 1000 पासआउट छात्रों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए जाएंगे।
- iv. एनआरएलएम में पंजीकृत 6000 महिला स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण पूरा किया जाएगा।
- v. बीज पूंजी निधि योजना, युवा स्टार्ट-अप ऋण योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, महिला उद्यमिता कार्यक्रम जैसी स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से और मिशन युवा योजनाओं के तहत युवाओं को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- vi. मॉडल करियर केंद्रों (एमसीसी) के माध्यम से नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए आउटरीच और परामर्श गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
- vii. युवा क्लबों के माध्यम से युवाओं का कौशल बढ़ाना।

कौशल विकास और रोजगार के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 176.98 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो 2023-24 के संशोधित आवंटन से 60.78 करोड़ रुपये अधिक है।

## 82.7 खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले:

- i. प्रधानमंत्री खाद्य अनुपूरक योजना के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति माह 10 किलोग्राम अतिरिक्त चावल प्रदान किया जाएगा।
- ii. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी की जाएगी।
- iii. जम्मू और कश्मीर में स्मार्ट पीडीएस की शुरुआत।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 445.25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो 2023-24 के संशोधित आवंटन से 65.79 करोड़ रुपये अधिक है।

## 83. अवसंरचना क्षेत्र

### 83.1 विद्युत क्षेत्र:

- i. बिजली की बेहतर उपलब्धता जो पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा देगी तथा इस प्रकार स्थायी रोजगार प्रदान करने एवं समानता को बढ़ावा देने के लिए निर्धनता को दूर करने, आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करेगी।
- ii. सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग।
- iii. हानि में कमी संबंधी कार्यों का कार्यान्वयन पहले से ही किया जा रहा है। प्रमुख रूप से एलटी-एबी केबलिंग कार्य और बिलिंग दक्षता में सुधार एवं एटी एंड सी घाटे को कम करने के लिए बेयर कंडक्टर को हटाना।
- iv. दोनों अक्षों (बालटाल और पहलगाम) पर पवित्र श्री अमरनाथ जी गुफा तक ग्रिड कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए भूमिगत केबल बिछाने की परियोजना का कार्यान्वयन
- v. उपभोक्ताओं को सुचारू और बाधारहित बिजली आपूर्ति के लिए 105.00 किमी एचटी/एलटी लाइन में सुधार।
- vi. अत्यधिक भारित विद्युत ट्रांसफार्मरों को राहत देने के लिए 35.45 एमवीए सब-स्टेशनों का संवर्धन/निर्माण और बार-बार ब्रेकडाउन तथा लोड शेडिंग से बचने के लिए अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना।



- vii. वितरण नेटवर्क के वोल्टेज विनियमन में सुधार लाने और मौजूदा उपस्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए 38,150 केवीए वितरण ट्रांसफार्मर उप-स्टेशनों का निर्माण/संवर्धन।
- viii. अत्यधिक भार वाले 11 केवी फीडरों को अलग-अलग करने के तहत 55 सीकेएम फीडरों को अलग किया जा रहा है ताकि फीडर स्थिरता को बढ़ाया जा सके।
- ix. एलटी नेटवर्क को मजबूत करने और बिजली की चोरी रोकने के लिए एलटी-एबी केबल द्वारा 14,000 सीकेएम जीर्ण-शीर्ण एलटी बेयर कंडक्टर का प्रतिस्थापन। स्मार्ट मीटरों की स्थापना के साथ एलटी-एबी केबल द्वारा बेयर कंडक्टर के प्रतिस्थापन से एटी एंड सी नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।
- x. 11 केवी स्तर पर टी एंड डी हानियों को कम करने के लिए 5,351.53 सीकेएम फीडरों को नए और बेहतर (मोटे) कंडक्टर के साथ नवीनीकृत किया जाएगा।
- xi. 66/11 केवी और 33/11 केवी सब स्टेशनों पर, पीक लोड घंटों में वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार के लिए 200 कैपेसिटर बैंक स्थापित किए जाएंगे और एमवीए खपत में कमी आएगी।
- xii. 210.60 एमवीए की क्षमता वृद्धि के लिए 31 रिसिविंग स्टेशनों (33/11 केवी) की योजना बनाई गई है।
- xiii. गुरेज के दूर-दराज और सुदूर क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करना।
- xiv. 132 केवी स्तर पर 04 जीएसएस का निर्माण किया जाएगा जो 2024-25 के दौरान 40 एमवीए, 2025-26 के दौरान 100 एमवीए और 2026-27 के दौरान 90 एमवीए की क्षमता बढ़ाएगा।
- xv. 132 केवी स्तर पर 16 जीएसएस को बढ़ाया जाएगा जो 2024-25 के दौरान 556 एमवीए और 2025-26 के दौरान 50 एमवीए की क्षमता बढ़ाएगा।
- xvi. 220 केवी स्तर पर 06 जीएसएस को बढ़ाया जाएगा जो 2024-25 के दौरान 90 एमवीए और 2026-27 तक या उससे पहले 720 एमवीए की क्षमता बढ़ाएगा।

- xvii. वर्ष 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से 3,014 मेगावाट स्थापित क्षमता की वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष 10,714.50 मिलियन यूनिट की डिजाइन ऊर्जा की संचयी वृद्धि।

विद्युत क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 2020.67 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो 2023-24 के संशोधित आवंटन से 698.28 करोड़ रुपये अधिक है।

### 83.2 जल शक्ति (जल आपूर्ति और सिंचाई)

- i. जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 3,256 जल आपूर्ति योजनाओं में से, 776 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष 2,480 योजनाओं को पूरा करने के लिए एफएचटीसी के साथ शेष 4.26 लाख घरों की कवरेज को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि नल के पानी के कनेक्शन के तहत 100% कवरेज प्राप्त की जा सके।
- ii. सभी 76 उपमंडल स्तर की प्रयोगशालाओं को एनबीएल मान्यता।
- iii. ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए प्रचालन और रखरखाव नीति शुरू करना।
- iv. कौशल विकास मिशन के माध्यम से एनजेएमपी के तहत लगभग 15,000 नल जल मित्रों का प्रशिक्षण।
- v. लंबित कार्यक्रम के तहत 450 जल आपूर्ति योजनाएं और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ऋण सहायता के तहत 159 जल आपूर्ति योजनाओं को वर्ष 2024-25 में पूरा करने का लक्ष्य है।
- vi. 225 बाढ़ नियंत्रण योजनाएं पूरी की जाएंगी, जो 1,467 हेक्टेयर भूमि को कटाव और बाढ़ के खतरों से बचाएंगी।
- vii. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) / नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (आरएमबीए) योजना के तहत 16 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरी की जाएंगी।
- viii. शाहपुर कंडी बांध परियोजना चालू वित्त वर्ष के दौरान चालू होने की संभावना है, जिससे जम्मू-कश्मीर को कठुआ और सांबा में 32186 हेक्टेयर भूमि पर 1150 क्यूसेक सिंचाई जल सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
- ix. तवी बैराज का शेष कार्य 2024-25 के दौरान पूरा किया जाना है।

- x. 2024-25 के दौरान 197 लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा किया जाना है, जिसमें 38,723 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन की परिकल्पना की गई है।

जल शक्ति विभाग के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 2661.96 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो 2023-24 के संशोधित आवंटन से 1129.03 करोड़ रुपये अधिक है।

### 83.3 आवासन और शहरी विकास:

- i. 65.33 एमएलडी क्षमता के सीवरेज शोधन वाले 05 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) कार्यान्वयनाधीन हैं।
- ii. अमृत 2.0 के तहत, 78 यूएलबीएस की 153 परियोजनाओं के लिए यूटी वाटर कार्ययोजना पूरी हो चुकी है। इसमें जल आपूर्ति कनेक्शन के लिए 99 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका लक्ष्य 2.25 लाख नए नल घरेलू कनेक्शन प्रदान करना है। साथ ही जल निकायों के कायाकल्प के लिए 50 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- iii. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 309 परियोजनाओं में से 223 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 86 परियोजनाओं के 2024-25 में पूरा होने की संभावना है।
- iv. पुराने शहर में अवरोधन और डायवर्जन नेटवर्क बिछाने के माध्यम से तवी नदी का प्रदूषण उन्मूलन।
- v. ट्रांसपोर्ट नगर, नरवाल, जम्मू और परिमपोरा श्रीनगर का पुनरुद्धार।
- vi. मार्च 2025 तक नगरपालिका ठोस कचरे का 100% स्रोत पृथक्करण।
- vii. जम्मू और श्रीनगर में रिंग रोड के साथ स्मार्ट एकीकृत सैटेलाइट टाउनशिप का विकास।
- viii. पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 200 ई-बसों की शुरुआत।
- ix. सांबा में बसंतेर और श्रीनगर/बडगाम में दूध गंगा नदियों की प्रदूषण उपशमन परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं और उधमपुर में देविका नदी के प्रदूषण उपशमन की परियोजना पूरी की जानी है।
- x. डल झील, श्रीनगर के साथ पश्चिमी फोरशोर रोड का निर्माण किया जाना है।
- xi. कटरा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से इंटर मॉडल स्टेशन (आईएमएस) विकसित किया जाएगा।

- xii. सभी 78 शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान को अंतिम रूप देना।
- xiii. डल-नीगीन झील में हाउसबोटों के सीवरेज नेटवर्क का विकास, जिसमें झील के अंदर बस्तियों का सीवरेज नेटवर्क भी शामिल है।
- xiv. गुज्जर नगर और डोगरा हॉल जम्मू में आधुनिक बूचड़खानों का निर्माण।
- xv. चरार-ए-शरीफ, बडगाम में सीवरेज योजना शुरू की जाएगी।

आवास और शहरी विकास क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 2760.26 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो 2023-24 के संशोधित आवंटन से 131.99 करोड़ रुपये अधिक है।

#### 83.4 कनेक्टिविटी:

- i. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)/शहरों और कस्बों की योजना/केंद्रीय योजना/केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ)/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ऋण सहायता/गड्डा मुक्त सड़क योजना के तहत 2024-25 के दौरान 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को ब्लैकटॉप किया जाएगा।
- ii. नाबार्ड के तहत 1023.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत 194 नई परियोजनाओं को वर्ष 2024-25 के दौरान निष्पादन के लिए शामिल किया जाएगा।
- iii. नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये की नई सड़क और पुल परियोजनाएं वर्ष 2024-25 के दौरान आरआईडीएफ किशत XXX के तहत शुरू की जाएंगी।
- iv. वर्ष 2024-25 के दौरान 60 चालू पुलों के चल रहे कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2024-25 के लिए सड़क और पुल क्षेत्र में पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 4061.74 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 118.87 करोड़ रुपये अधिक है।

### 83.5 औद्योगिक विकास:

- i. निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 46 नई औद्योगिक संपदाओं का तेजी से विकास।
- ii. जम्मू और कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (जे एण्ड के आरईजीपी) के तहत, वर्ष 2024-25 के दौरान 1372 इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- iii. उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए नई स्टार्ट-अप नीति पेश की जाएगी।
- iv. मौजूदा औद्योगिक संपदाओं में अवसंरचना का उन्नयन।
- v. निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति में संशोधन किया जाएगा।
- vi. इस वर्ष 324 इकाइयों में उत्पादन शुरू होने की संभावना है जिनमें 18,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है।

वर्ष 2024-25 के लिए उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र में पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 534.62 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 138.36 करोड़ रुपये अधिक है।

### 83.6 विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

- i. पीएम-कुसुम घटक "सी" के तहत चरणबद्ध तरीके से 4,000 एसी कृषि पंपों को सौर पंपों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- ii. सरकारी भवनों पर लगभग 04 मेगावाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 22,494 सरकारी भवनों को चरणबद्ध तरीके से 100% सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा।
- iii. पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डल झील, श्रीनगर में प्रदर्शन के उद्देश्य से 100 किलोवाट तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
- iv. घर के अंदर वायु प्रदूषण और ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 उन्नत बायोमास कुक-स्टोव प्रदान किए जाएंगे।
- v. सौर पार्कों के विकास के लिए भूमि बैंक की पहचान की जाएगी।
- vi. विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएडीपी) के तहत पूर्ण सौरीकरण के लिए पर्यटक और धार्मिक स्थानों को शामिल किया जाएगा।
- vii. श्री अमरनाथ जी यात्रा के सभी मार्गों और शिविरों का सौरीकरण।
- viii. कठुआ में जैव-प्रौद्योगिकी पार्क का प्रचालन।

- ix. स्नातक और पीजी छात्रों के लिए विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्ति।
- x. उत्कृष्ट शोधकर्ताओं के बीच युवा वैज्ञानिक पुरस्कार/अध्येतावृत्ति।

वर्ष 2024-25 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 159.80 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 71.80 करोड़ रुपये अधिक है।

### 83.7 परिवहन क्षेत्र:

- i. कोट भलवाल, जम्मू में आईडीटीआर के वर्ष 2024-25 में पूरा और चालू होने की संभावना है।
- ii. सांबा, जम्मू में निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र संस्थान (आईसीसी) के वर्ष 2024-25 में पूरा होने की संभावना है।
- iii. सार्वजनिक परिवहन वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीएलटीपी) का कार्यान्वयन।
- iv. निजी क्षेत्र में मोटर वाहनों की फिटनेस के परीक्षण के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) स्थापित किए जाएंगे।
- v. समय सीमा समाप्त वाहनों (ईएलवी) के लिए वैज्ञानिक तरीके से वाहन के विखंडन और स्क्रेपिंग संबंधी कार्यों के संचालन के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की नीति की शुरुआत।
- vi. टीआरसी, श्रीनगर में आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण।

वर्ष 2024-25 के लिए परिवहन क्षेत्र में पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 22 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 8.11 करोड़ रुपये अधिक है।

### 84. वर्ष 2024-25 के लिए बजट:

- i. कुल सकल प्राप्तियों का अनुमान 1,51,526 करोड़ रुपये है, जिसमें 33,136 करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिम और ओवर-ड्राफ्ट का प्रावधान शामिल है। इन प्राप्तियों को देखते हुए कुल सकल व्यय 1,51,526 करोड़ रुपये अनुमानित है।

- ii. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल निवल बजट अनुमान 1,18,390 करोड़ रुपये है, जिसमें अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के प्रावधान शामिल नहीं हैं। अपेक्षित राजस्व प्राप्तियां 98,719 करोड़ रुपये और पूंजीगत प्राप्तियां 19,671 करोड़ रुपये हैं। इसी तरह राजस्व व्यय 81,486 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 36,904 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- iii. कर और गैर-कर दोनों का स्वयं का राजस्व 30,586 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता के रूप में 42,278 करोड़ रुपये और सीएसएस/पीएमडीपी के रूप में 12,502 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- iv. तदनुसार, वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों के संबंध में जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक संख्या (01) को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र समेकित निधि से 1,51,525.7743 करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ।

#### 85. राजकोषीय संकेतक:

- i. वर्ष 2024-25 के लिए कर/जीडीपी अनुपात 7.91% अनुमानित है जो पिछले वर्ष के 6.56% से अधिक है।
- ii. वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 3.0% रहने का अनुमान है। यह वर्ष 2023-24 (संशोधित अनुमान) के 5.3% से काफी कम है। यह कमी केंद्र सरकार से मिली विशेष आर्थिक मदद की वजह से संभव हुई है।
- iii. वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद 2,63,399 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% की वृद्धि दर्शाता है।

86. अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को इस गरिमापूर्ण सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करती हूं।

**Budget 2024-25**  
**of**  
**the Union Territory of Jammu and Kashmir (With Legislature)**

**Speech of**  
**Nirmala Sitharaman**  
*Minister of Finance*

**Mr. Speaker Sir,**

1. I am honoured to place the Budget of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the financial year of 2024-25 before this august House. Jammu and Kashmir has witnessed unprecedented socio-economic development since the historic reforms initiated in August, 2019. Triggered by these reforms, the Union Territory government has pursued the path of accelerated and inclusive growth to fulfill the aspirations of common man. This has ensured remarkable progress encompassing entire governance - including the developmental activities, public administration and security matters - which has positively impacted every resident irrespective of caste, creed or religion.
2. Since 2019, the entire region has witnessed an era of peace, progress and prosperity. Life has returned to normalcy in Jammu and Kashmir after over three decades of turmoil. Schools, colleges, universities, hospitals and other public institutions are functioning efficiently without any strikes or any kind of disturbances during the last four years. The earlier practice of daily hartals, strikes, stone pelting and bandhs are things of the past now.
3. This has also enabled its citizens to discover their untapped potential, address the aspirations of young generation and contribute wholeheartedly in the development journey. The people of Jammu and



Kashmir participated enthusiastically in the recently held Lok Sabha elections. The record voter turnout is testimony to the meticulous and impartial conduct of elections, the robust democratic spirit and civic engagement of the people as also to the success of the reforms initiated in the year 2019. Unprecedented participation by the people of Jammu and Kashmir in the democratic exercise during the Parliament Elections is a clear indication that after decades of turmoil, the people are witnessing a positive and conducive environment to achieve their aspirations.

4. Hon'ble Speaker Sir, I am confident that Jammu and Kashmir is on a right trajectory and would emerge as one of the most developed region and would contribute immensely to our Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji's vision of Viksit Bharat.

#### **Complete Breakthrough in the law and order scenario**

5. The Union Territory government remains committed to dismantle terror sponsoring ecosystem. The policy of zero tolerance has been adopted against terrorism and security forces have foiled the repeated efforts of those sponsoring proxy wars. The unstinted efforts and sacrifice of security forces have only boosted the confidence and resolve of our society to remain united, courageous and disciplined to fight against those who are promoting terrorism.
6. While fighting the terrorism, the government has also focused on improving overall law and order situation in Jammu and Kashmir. The defining characteristic of the security situation in Jammu and Kashmir which has a direct bearing on day-to-day life of common citizens is 'street violence' which was a methodical and regular phenomenon pre 2019. The street violence, engineered and orchestrated by terrorists and secessionist networks is now a thing of past. Students are happy as there are no more school closures, businessmen are happy as there are no more bandhs and hartals, youngsters are happy as peace is bringing lots of economic opportunities, mothers are happy as their children are safe

now, citizens are happy that all services like hospitals, public transport, civic services etc. are within their reach now. This harmonious law and order situation has helped the government to initiate and implement socio-economic development.

### **Improving Fiscal Situation**

7. Mr. Speaker Sir, while analyzing the fiscal situation of Jammu and Kashmir, we observed that due to historical challenges in financial management, it has a legacy of very high fiscal stress. This is aggravated by the committed nature of the major expenditures not supported by proportionate increase in its revenues. Its dependence on central grant is to the tune of around 70% of its total expenditure. The perpetual fiscal stress leads to frequent use of ways and means advances and overdraft.
8. This year the Government of India decided to correct this historical aberration by providing adequate financial support to Jammu and Kashmir coupled with reforms to come out of the perpetual fiscal stress. I am happy to mention here that to correct the complex fiscal issues of Jammu and Kashmir, a special central assistance of ₹17,000 crore has been worked out.
9. It is observed that around 11% of budget of Jammu and Kashmir is used for Police. Such expenses on policing being unavoidable, leaves limited space for spending on development and welfare projects. I am happy to inform this august House that the Union Government has agreed to take the entire burden of budget of police from Union Territory of Jammu and Kashmir. The Central Government will now provide for the salary, pension and other costs of Jammu and Kashmir Police for which an allocation of ₹12,000 crore has been made in the annual budget.
10. In addition, a lump sum special grant of ₹5,000 crore as additional central assistance is being provided in the current financial year.

11. As a result of this ₹17,000 crore of central assistance, the fiscal deficit to GDP ratio will be 3.0% in the FY 2024-25 well within the target. This unprecedented assistance would lead to complete improvement in fiscal position enabling the Government of Jammu and Kashmir to correct the legacy of financial challenges and work towards fulfilling the developmental needs and aspirations of the people, while maintaining stable fiscal health.
12. Mr. Speaker Sir, the complete turnaround of Jammu and Kashmir Bank post 2019 is a success story. The Union Territory government being the promoter of the Jammu and Kashmir Bank has endeavored to improve its capital adequacy and corporate governance. The Union Territory government facilitated the reforms to limit concentration of power, professionalization of management and induction of professional experts in the Board. When the Bank suffered losses due to the financial indiscipline and the consequent high NPAs, the Union Territory government reinforced the Bank by infusing substantial equity capital over 2019 to 2022. These steps facilitated transformation of the Bank's financial health and enabled its business growth and transition out of losses of the pre-2019 period. The success of reforms facilitated by the government is exemplified in the business results of the Bank and its turn-around in the last five years. The Union Territory government has further decided to eliminate the pension overdues for safeguarding the financial position of the bank.
13. Union Territory has witnessed profound ameliorative, affirmative and progressive changes in the last five years. The Government of Jammu and Kashmir is working on the mantra of "Reform, Perform and Transform". This has led to several path-breaking initiatives to unlock economic and industrial potential, improve quality of life, promote social and financial inclusion, fortify law and order machinery, decentralize governance systems, improve efficiency and transparency of public expenditure, upscale revenue generation, minimize wasteful expenditure, and step up infrastructure development. Some of these are elaborated in the following paragraphs:

## Improving Transparency and Efficiency in Governance

14. The government has adopted General Financial Rules to ensure discipline in approval, bidding and execution processes. IT reforms were initiated to streamline financial management by ensuring work-wise allocation of funds through BEAMS (Budget, Estimation, Allocation and Monitoring System) platform. We universalized procurement of goods and services through Government e-Market Place (GEM) to enable competitive and cost-efficient purchases. The Union Territory government received the Gold medal for its major progress in GEM based procurement.
15. The government ushered transparency in land administration through '*Aapki Zameen Aapki Nigrani*' portal which enables online access to land records. Registration of land revenue documents was made online to boost citizen convenience and revenues. The Union Territory government also introduced the EMPOWERMENT / JANBAGHIDARI portal for transparency about developmental works. The portal enables citizens to view all ongoing works online and improves accountability in work execution. The Union Territory government started physical verification of all works as also online tracking of work progress with geo-tagged photographs through the PROOF (photographic record of on-site facility) platform.
16. **Direct Benefit Transfer** - The efforts of the Union Territory to saturate all the individual beneficiary schemes and ensure 100% Aadhar seeding for *beneficiaries* have enabled direct transfer of funds to their accounts. More than ₹6,000 crore was seamlessly disbursed to over 70.46 lakh beneficiaries through over 50 Direct Benefit Transfer (DBT) based welfare schemes (both cash and kind) by March, 2024. Jammu and Kashmir recorded 74 crore 42 lakh e-transactions in 2023-24, averaging over 20 lakh electronic transactions registered daily, which is higher than many States.

17. *Aadhar* seeding has been undertaken systematically for cleaning databases of various welfare schemes. Through bio-metric verification and provision of e-POS machines, about ₹230 crore has been saved through DBT and Aadhar based verification under ration supply. Similarly, savings of over ₹200 crore have been ensured by leveraging DBT under social security schemes.

### **Unlocking Economic and Industrial Potential**

18. **Agriculture and Allied sectors** – Agriculture and allied sectors need to be viewed as sustainable sources of livelihood. For this, path-breaking initiatives have been taken to further the interests of farmers, leading to improvement in their incomes. The Government is working towards bringing all farming lands under two-crop patterns to ensure sustainable income throughout the year. The government has worked for improving efficiency in land utilization by promoting high density plantations. 17,390 hectare under medium density and 663 hectare under high density fruit plantation have been added to increase the income of apple growers. Fresh fruit and dry fruit production has increased from 20.06 lakh MTs in the 2018-19 to 26.43 lakh MTs in the 2023-24, recording an increase of about 10% during these years.
19. The Controlled Atmosphere (CA) storage capacity has been augmented from 1.14 LMT in 2018 to 2.70 LMT in 2024. Twelve (12) CA stores with capacity of 60,000 MTs have been completed during 2023-24 and seven (7) new CA stores with capacity of 25,000 MTs will be added during 2024-25. In order to ensure economic security for farmer families, a total of 10.90 lakh Kisan Credit Cards (KCCs) have been distributed so far. Total 17 mandis have been integrated with electronic National Agricultural Market (e-NAM) and 51,748 farmers and traders, including 98 FPOs have been registered. Under the PM Kisan Samman Nidhi Yojana, more than ₹3,000 crore have been deposited directly into the bank accounts of 12.68 lakh eligible farmers.

20. The Union Territory government is revitalizing the agriculture sector by investing in quality seeds, farm mechanization, high density plantation, cold storages, and farmers insurance. To this end, the government rolled out 29 interventions in Agriculture and allied sectors under the “Holistic Agriculture Development Programme” with a substantial allocation of ₹5,013 crore. This programme is expected to double the value addition from these sectors, boost the sectoral growth rate to 11%, create employment opportunities for over 2.88 lakh youth and establish around 19,000 enterprises within the next five years.
21. With the objective of linking Primary Agricultural Credit Societies (PACS) electronically with District Central Cooperative Banks, and bringing about transparency in credit provided to farmers and members of cooperatives, 537 PACS have been prioritized for revitalization. The government is aiming to have one approved PACS in every Panchayat so that it operates inclusively and supports local economy. Artisans and weavers are being provided credit card scheme with an attractive interest subvention of 7% for a period of 5 years.
22. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin, 3.40 lakh houses have been sanctioned and construction of 2.10 lakh houses has been completed. 5 marla land was allotted to 477 landless families for house construction. The number of annual works under MGNREGA also increased from 54,300 in 2019-20 to 1,24,623 by the end of FY- 2023-24.
23. **Tourism** – Tourism is a way of life for Jammu and Kashmir that contribute massively to the local economy. This paradise on earth witnessed a record flow of 2.11 crore tourists during the year 2023. Around 1.02 crore tourist have already visited in 2024 till June, 2024. Apart from popular tourist destinations like Gulmarg and Pahalgam, there is a significant flow of tourists in offbeat destinations, like Shiv Khori, Mansar-Surinsar, Patnitop, Dudhpathri, and Lolab. Revival of tourism in border areas, like Gurez and Suchetgarh, has strengthened the local economy.

24. After granting industry status to the tourism sector, investment in this sector has seen enormous growth. Tourism department invested in improving tourism infrastructure and services and promoting tourist attractions. To accommodate the increasing tourist flow and provide quality services, the Union Territory government introduced the home stay policy. 1,942 home stays with the bed capacity of 14,180 have been registered so far in Jammu and Kashmir. The Union Territory is emerging again as a major attraction for film producers from around the world, establishing Jammu and Kashmir as a prime film-making destination. 102 films/web series have been shot in Jammu and Kashmir in the year 2023.
25. **Industrial Development** - The government is making steadfast efforts to attract new investment, create employment opportunities for youth, develop backward regions and expand existing industrial units. We launched the Jammu and Kashmir Industrial Policy 2021-30, the Industrial Land Allotment Policy 2021-30, JK Start-up Policy 2024-27, Private Industrial Estate Development Policy 2021-30, Wool Processing, Handicrafts and Handloom Policy 2020 in this direction.
26. The Central Government has rolled out the New Central Sector Scheme (NCSS) since 2021 with an outlay of ₹28,400 crore for industrial development in Jammu and Kashmir. The proactive policies of the Union Territory government coupled with the NCSS benefits ensured investment realization of ₹3,389 crore during 2023-24. Total 889 units with investment of ₹18,185 crore and employment of 46,857 have already started work on the ground. Out of these 889 units, 324 units with investment of ₹9,538 crore are expected to come into production during 2024-25.
27. Apart from the existing 64 industrial estates, 46 estates are being developed to fulfill the goal of 'Made in Jammu and Kashmir'. Karkhandar Scheme is being implemented to provide fresh impetus to

the craft industry. The government has granted recognition to 656 start-ups in the past year.

28. To provide new identity to the products of Jammu and Kashmir on the global handicraft map, GI tagging has been approved for 10 crafts, and the process for GI registration of 12 other products is underway. A leading e-commerce company has developed a robust web portal that will make handicrafts of Jammu and Kashmir available in the global market. Handloom and Handicraft exports have doubled from ₹563 crore in 2021-22 to ₹1,162 crore in 2023-24.

### **Improving quality of life**

29. **Healthcare** - Infrastructural up-gradation of health sector has resulted in unprecedented improvements in public health services. With the construction of more than 4,000 health facilities/institutions, broadly conforming to the Indian Public Health Standards (IPHS), including two AIIMS, two Cancer Institutes and two Bone and Joint Hospitals have resulted in achievement of significant milestones in the field of healthcare.
30. There has been an unprecedented expansion in medical education with establishment of 9 new Medical Colleges. The capacity of MBBS seats has increased from 500 to 1,300. 26 B.Sc nursing colleges and 19 BSc paramedic colleges have been added in public and private sector.
31. Through the SEHAT initiative, universal health insurance of ₹5 lakh per family has been provided, free of cost, to all residents. Over 85.49 lakh persons have been issued the Golden cards and about 251 hospitals are empaneled under **AB-PMJAY-SEHAT** scheme for providing quality health care. About 12.90 lakh treatments have been provided so far worth ₹2,285 crore which have provided services to 3.60 lakh beneficiaries since August 2020. The scheme has been a game changer for the public at large as it provided the financial support to treatment seekers for



availing timely intervention required for leading a healthy life. Tele-medicines services have also been introduced.

32. The Union Territory government has started over 3,104 health and wellness centers since 2019. Jan Aushadhi centres have been expanded from 38 in 2019 to 270 by March 2024. Over 489 new ambulances have been mobilized for emergency care. These measures have helped the Union Territory to reduce IMR from 22.0 as per National Family Health Survey - 4 to 16.3 as per National Family Health Survey – 5 as also improve sex ratio at birth from 927 as per National Family Health Survey - 4 to 976 as per National Family Health Survey - 5.
33. **Education** –The congenial environment in the Union Territory since 2019 has enabled rapid increase in enrolment of students in primary, middle and secondary government schools from 12.40 lakh in 2019-20 to over 14.18 lakh in 2022-23. The Union Territory government has embarked on the initiative to provide early childhood education by starting development of 15,000 pre-primary schools with enrolment of 1.80 children.
34. Under the Pradhan Mantri Schools for Rising India (PM-SHRI) Yojana, approval has been granted for the upgradation of 389 schools in the first and second phase. Thrust has also been provided to girls' education. To fulfill the commitment to universal education, 46,000 out-of-school children have been identified, enrolled in various schools and mainstreamed. The punctuality and working discipline of teaching staff was enhanced by installing facial recognition based attendance systems in all the schools. The capacity of polytechnic colleges is being augmented with 600 additional seats.
35. National Education Policy 2020 is operationalized and the four year undergraduate programmes have been initiated in all the colleges. The Union Territory witnessed spurt in higher education with 51 new degree colleges getting established since 2019. To facilitate online education, electronic content for 50 subjects has been developed and uploaded. The

Union Territory government instituted the unique feedback portal to evaluate teachers and institutions. The college and university infrastructure got a major boost through projects under Rashtriya Uchhatar Shiksha Abhiyaan (RUSA) funding. The prestigious national institutes, like IIT Jammu and IIM Jammu, were made operational by providing land and other incentives.

36. **Sports** - After three decades, international tournaments have started in Jammu and Kashmir. Now Jammu and Kashmir has positioned itself as a premier sports destination in the country. The reforms undertaken in years 2019 have ushered revolution in sports and participation of youth. There has been a complete transformation of sports infrastructure in the Union Territory with construction of 100 Khelo India Centres, development of indoor sports complexes across the Union Territory besides completion of 702 sports related projects. Multipurpose indoor sports halls have been constructed in almost every district. Playfields have been developed in every panchayat. Floodlighting and synthetic turfing is being installed in several stadia.
37. Centres of Excellence have been established in Canoeing, Rowing and Fencing in both Jammu and Kashmir divisions. Synthetic Hockey Turf, KK Hakku Stadium, Jammu and Synthetic Hockey Turf, Pologround, Srinagar were constructed and approved by Federation of Indian Hockey (FIH). Synthetic football turf is being developed at Khel Gaon, Nagrota. Jammu and Kashmir is emerging as winter sports capital of the country. 04 events of Khelo India winter games have been organized in Gulmarg - the world famous winter destination, since March 2020.
38. **Employment** – The government had conceived a pioneering initiative- Mission Youth to transform youth of Jammu and Kashmir into ambassadors of peace and development through structured systematic interventions in the domains of livelihood generation, education and skill development, counseling, sports and recreation. Under the Mission Youth initiatives of Mumkin, Tejaswani, and Spurring Entrepreneur

programme, financial assistance is being provided to large number of youth and women entrepreneurs.

39. We also launched a massive recruitment drive. Since August 2019, total 38,384 persons were recruited in government sector in a fair, merit based, transparent, and expeditious manner. To secure the future of workers in the unorganized sector, more than 34 lakh labourers have been registered on the e-Shram portal. A total of 7.66 lakh self-employment/livelihood opportunities generated/ strengthened since the year 2021-22, till date.

### **Expanding social and financial inclusion**

40. To ensure quality education of the new generation students from the tribal community, 25 hostels are being constructed. Initiatives such as livelihood units, skill development, and professional coaching are providing new opportunities to tribal youth. The government has undertaken significant initiatives for tribal welfare in the areas of health, education, culture, literature, infrastructure development and livelihoods. Transit facilities were provided to migratory tribal communities. 8 new hostel buildings, 285 smart schools, 6 Eklavya Model Residential Schools were developed. The government provided dedicated coaching facilities, skill development to 2,000 tribal youth and scholarships to 46,000 tribal students. After two decades of anxious wait, forest rights were granted to tribal communities.
41. The Union Territory government expanded its social security cover for widows, old aged and physically challenged persons. The monthly assistance/pensionary benefits were expanded from around 5.0 lakh beneficiaries in 2014-15 to about 8.61 lakh in 2023-24. Under the merit cum means Minority Scholarship schemes 15,957 students have been covered during 2023-24. Similarly 9,879 students have been covered under Scheduled Caste Scholarship schemes during 2023-24.

42. The Union Territory government has prioritized setting up of brick and mortar branches in the unbanked villages with population more than 3,000. Of the 10 villages prioritized for providing banking services through brick and mortar branches, 9 villages stand covered. 167 villages which did not have banking services within the radius of 5 km, are now covered through banking correspondents or brick and mortar branches.
43. Under the PM-SVANidhi Scheme, special credit facility with a working capital has been disbursed to 26,596 street vendors. Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), ₹8,063.19 crore loans have been disbursed to 3,63,817 beneficiaries during FY 2023-24 by all the banks. As on March 31<sup>st</sup>, 2024, concessional credit of ₹7,686 crore have been sanctioned by banks to 8.83 lakh KCC (Crop) account holders. ₹1,559 crore have been sanctioned to 2 Lakh KCC-AHF (Animal Husbandry and Fisheries) beneficiaries.
44. **Women Empowerment** - The government has expanded coverage of “Ladli Beti” from 16,095 cases in 2017 to 1,61,552 cases upto 2023-24. The financial assistance for the deserving girl children increased from ₹24 crore to ₹847 crore during this period. Under the Marriage Assistance scheme, 1,04,326 poor girls were provided financial assistance of ₹394 crore since 2015-16 to 2023-24.
45. Over seven lakh women are associated with about 90,000 self-help groups. Training has been provided to around three lakh women farmers. Women farmers have established nearly two lakh agriculture nutrition gardens to meet the nutritional needs of their families. The Rural Livelihood Mission is now working to promote ‘Lakhpati Didis’ across the Union Territory and establish new micro-startups.
46. The Jammu and Kashmir Reorganization (Second Amendment) Act, 2023 now provides for reservation of one-third of all elected seats in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly for women.

## Accelerating Infrastructure Development

47. With support of the Central government, the Union Territory stepped up capital investments to accelerate infrastructure development. Under the Prime Minister's Development Package, ₹49,975 crore has been received for 53 projects, of which ₹48,359 crore has been utilized till May, 2024 and 35 projects are completed or near completion.
48. 1646 languishing projects with cost of ₹3,268 crore were prioritize and completed through accelerated funding.
49. **Power Sector** - The Union Territory government aims to expand its installed hydro power capacity from 3500 MW to about 6500 MW till 2026-27. For this, it has partnered with NHPC to develop the 624 MW Kiru, 850 MW Ratle, 1000 MW Pakal Dul and 540 MW Kwar projects. The Central government provided ₹2430.60 crore for equity contribution of the Union Territory for these projects.
50. We are also pursuing development of further 04 hydro power projects of 3284 MW capacity, namely Sawalkote (1856 MW), Dul Hasti stage-II (258 MW), Uri-I stage -II (240 MW), and Kirthai-II (930 MW), with expected investment of about ₹50,000 crore. The Union Territory will also benefit from its share of free power, long term supply of stable power, expansion of economic activities, and creation of job opportunities. The government is also stressing on development of small hydropower projects and rooftop solar power projects.
51. The massive expansion of transmission capacity by an around 50% during 2019-24 has enabled the expansion of electric supply to interior villages. Gurez Valley in northern Kashmir was connected to the electricity grid. The process of installing smart pre-paid meters is underway in mission mode. There has been successful loss-reduction of 15% in metered areas with 5.74 lakh smart meters installed by June 2024.

52. **Physical Connectivity** – By leveraging Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) and Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) funding, the Union Territory government rapidly expanded road network to habitations. Considering data of the 2001 census, all rural settlements having population 250 + have been connected under the Prime Minister's Gram Sadak Yojana, and process of proving connectivity to remaining villages as per the census 2011 is under progress.
53. 7,886 km of roads to various villages have been constructed under PMGSY in the past four years. Through close monitoring and accelerated execution, the road construction speed has doubled. While 2,914 projects got completed and 9,382 km of roads were blacktopped during 2017-20, over 9,235 projects were completed and 21,799 km roads got blacktopped during 2020-24. This has substantially improved road connectivity to remote villages and substantially reduced travelling times in this Himalayan UT.
54. The work on semi-ring road for Jammu (58 km) is nearing completion, while the four-laning of semi-ring road for Srinagar has achieved 48% physical progress. Work on upgradation of Srinagar-Baramulla-Uri road with bypasses for Pattan and Baramulla towns has been taken up at a cost of ₹3,554 crore. Constructing 8.45 km long twin tube Qazigund-Banihal tunnel has substantially saved time required on the Jammu-Srinagar National Highway. Works on the 13.15 km 2-lane bi-directional Zojila tunnel and on the 6.40 km Z-Morh tunnel on Srinagar-Leh road, at cost of ₹4,509 crore and ₹2,379 crore respectively, are at advanced stages. Project for Sudhmahadev–Dranga tunnels I and II (8 km) on NH- 244 is under tendering on EPC mode for an amount of ₹3,703 crore. Work on the 1.574 km Khellani Bypass tunnel on NH 244 has achieved 67% physical progress, while that on the 495 m tunnel of NH 244 from Chamoti to Drabshalla is 50% complete.
55. **Rail Connectivity** - The work on Jammu-Udhampur-Srinagar-Baramula railway is in the final stages of commissioning. The railway lines

between Banihal-Khari-Sumber-Sangaldan section (48 km) and Reasi-Sangaldan Section (46 km) and the electrification of Baramulla-Srinagar-Banihal-Sangaldan section (186 km) have been completed during 2023-24. With this, 255 km out of this railway line (272 km), which is crucial from socio-economic and strategic dimensions, will get commissioned. The work for remaining section from Katra- Reasi (17 km) is expected to be completed in 2024-25.

56. **Irrigation and Water Supply** – The work on Tawi Barrage project envisaging creation of an artificial lake of 1.41 MCM pondage to enhance tourism potential of Jammu has been recommenced. Project execution is in full swing and will be completed during this financial year at an estimated cost of ₹64.80 crore.
57. Work on Shahpur Kandi Dam project has progressed well and will help Jammu and Kashmir get its due share of 1,150 cusec water from the river Ravi.
58. Under Jal Jeevan Mission, Jammu and Kashmir has planned 3,256 schemes at an estimated cost of ₹13,000 crore. Out of 18.69 lakh rural households, 15.08 lakh (80.64%) rural households have been provided functional household tap connections. The Union Territory has saturated/provided 100% household tap connections in two districts – Srinagar and Ganderbal.
59. Flood Management program of river Jhelum and its tributaries (Phase-I) was commissioned to increase the carrying capacity of Jhelum from 31,800 cusec to 41,000 cusec. The Phase-II of this Project has commenced at sanctioned cost of ₹1,623 crore. The work for construction of entry and exit gates of Hokersar wetland will be soon completed.
60. **Urban Development and Housing** - Under Smart City Mission, 309 projects are approved for revamping of urban infrastructure in both the smart cities. These include 20 projects at a cost of ₹666 crore on PPP

mode and 55 projects at a cost of ₹3,475 crore on convergence mode. Projects like development/ up-gradation of Srinagar Square, Lal Chowk, Jhelum river front, redevelopment of Polo view high street, traditional Souq market, craft centre Batmaloo, northern foreshore road, lakefront from Nishat to Naseem Bagh Habak, improvement of road from Dogra Chowk to KC chowk, Apsara road high street, development of Canal road, Talab Tillo street development from Mubarak Mandi to Raghunath Bazaar etc. have been undertaken.

61. Under green urban transport initiative, 200 e-buses under Smart City mission have been introduced and are operational on the designated inter/intra city routes. Further, 200 more e-buses approved under PM e-bus Sewa shall be introduced in near future. Also, environmental friendly e-Rickshaws/e-Autos, public bicycles were introduced in both capital cities.
62. Residential colonies are being developed at Birpur (Samba), Padgampura (Pulwama), Chatterhama (Ganderbal), Bhalwal, Roop Nagar and Chowadhi Jammu for EWS beneficiaries. Besides, Integrated Mass Housing Colony at Watapora (Bandipora) and Satellite Township at Rakh-Gund Aksha are also being developed. Further, under AMRUT funding, 82 projects were completed which include laying of 74 km of sewer lines with 13,000 sewerage connections, development of Parking spaces for 1,596 vehicles, construction of 6 km of pedestrian walkways, laying of 104 km of storm water drains, and development of 46,165 square meter of green spaces. 3 km of 1200 mm diameter water supply line to 30 MGD water treatment plant at Rangil was laid for establishing assured water supply for 3 lakh souls.

### **Decentralizing Governance and Strengthening Public Outreach**

63. The 73<sup>rd</sup> Amendment to the Constitution was fully adopted after the 2020 amendment to the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989. The Panchayati Raj Institutions (PRIs) were empowered and twenty-seven



subjects were transferred to these institutions for decentralized planning, decision making and supervision.

64. The elections were held for various tiers of PRIs in 2019, which facilitated the release of the Finance Commission grants. Since then, the Gram Panchayat based Development Plans (GPDPs) have been framed through participatory planning and are being executed to address local needs. Power to grant building permissions in rural areas has been delegated to PRIs at panchayat level.
65. We are committed to empower local government institutions and strengthen grassroots governance. In this direction, the Union Territory government is making preparations to conduct local body elections, including those towards the constitutional obligations for providing reservations.
66. After the re-organization, Jammu and Kashmir has embarked on the ambitious Back to Village (B2V) programmes for reaching out to the people at the grass-roots and understanding their felt needs. From 2018-19 to 2023-24, five rounds of this B2V programme have been conducted, wherein senior officials toured to all villages. This initiative has become quite popular as such tours and local interactions helped redress the grievances of common people.
67. As a sequel to B2V programme, the “Jan-Abhiyan”, “Public Darbars” and “Block Divas” are being conducted for bringing welfare programmes at the door steps of the people. Further, the “Aspirational Block Development” and “Aspirational Panchayat Development” programmes were started for bridging the developmental gaps of the most backward blocks and panchayats.

### **Legal Reforms for Social Justice**

68. All the provisions of the Constitution and the benefits of the important central legislations, like the Right of Children to Free and Compulsory

Education Act, 2009, the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1954, the Whistle Blowers Protection Act, 2014, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and other important central legislations are now enjoyed by the people of Jammu and Kashmir

69. These reforms have also enabled extension of voting rights for the assembly and local body elections to the hitherto deprived sections of the society, like West Pakistani Refugees, Safai-Karamcharis and Valmikis who were residing in Jammu and Kashmir for decades. Further, these reforms helped the West Pakistani Refugees, Safai-Karamcharis and Valmikis, children of local women married outside Jammu and Kashmir and other similarly situated persons get domicile certificates thereby eliminating their deprivation and discrimination.
70. Jammu and Kashmir Reservation Act, 2004 was amended to extend the reservation to the persons residing in the areas adjoining actual line of control and adjoining International Border for education and employment as also to bring “Other Backward Castes” of Jammu and Kashmir at par with other parts of the country.
71. As part of affirmative action, reservation has been extended to Pahari Speaking People and the economically weaker sections for their upliftment. The Reorganization Act, 2019 was amended to provide representation in the Legislative Assembly by way of nomination to Kashmiri migrants and displaced persons from areas of Jammu and Kashmir under occupation of Pakistan.
72. We have also provided for reservation of one-third of all elected seats for women in Jammu and Kashmir Legislative assembly through Jammu and Kashmir Reorganization (Second Amendment) Act, 2023.

## **e-Governance initiatives**

73. The Union Territory government has ushered transformation towards digital governance through the e-Office system. Over 450 government offices upto district level have shifted from physical files to e-filing system. This adoption enabled the government to end the darbar move and save huge expenditure annually.
74. The Union Territory achieved a remarkable feat by offering over 1,100 citizen centric services online and thus securing the national recognition in the NeSDA (National e-Service Delivery Assessment) rankings. This digital revolution has enhanced accountability, transparency, and efficiency in governance.

## **State of Economy in 2023-24**

75. Jammu and Kashmir is one of the fastest growing Union Territory. This is testified by strong growth in revenue collection during 2023-24. The revenue collection under Goods and Services Tax touched ₹8,064 crore in 2023-24 with 12 percent growth over such revenues in 2022-23. The revenue from motor spirit taxes reached ₹1,631 crore in 2023-24 against the receipt of ₹1,554 crore in 2022-23. The stamp and registration revenue has increased to ₹678 crore in 2023-24 against ₹557 crore during 2022-23, showing a growth of 22 percent. The excise collection touched ₹2,490 crore in 2023-24 against ₹1,794 crore during 2022-23, registering a growth of 39%. The economy remains on right track with the GDP growth for financial year (2023-24) is expected to be 7.5%.
76. The Union Territory government has followed fiscally prudent policies while focusing on equitable growth in all the sectors. For sustaining the developmental initiatives, focused enforcement and dealer outreach drives were undertaken. The government pursued the tax and non-tax avenues judiciously.

77. Dealer registration under GST has been expanded from about 72,000 in 2018-19 to over 2,00,000 in 2023-24. Capacity building of taxation staff was undertaken with support of Institute of Chartered Accountants. For stemming GST leakages, mechanism for tracking purchases was developed. For tracking GST deduction under capital works and improving tax realization, GSTN verification has been linked with bill payment system.
78. The Union Territory government notified the new excise policy and established all the planned vends through the transparent system of auctions in allotment of liquor vends. With support of NIC, the Union Territory initiated the e-Stamping system for registration of documents. This enhanced stamps and registration revenues from ₹190 crore in 2018-19 to ₹678 crore in 2023-24. The e-Abgari platform is being strengthened for tracking the supply chain and enhancing excise revenue. These measures have enabled revenue from GST, Excise and Stamps to register healthy growth.
79. The non-tax collection has also shown significant growth and resilience. Special focus was given on installing aerial bunching cables and smart meters for tracking power consumption. The installation of around 5.74 lakh smart meters has impacted consumer behavior and limited power consumption and also improved tariff revenue by about 10% in 2023-24.
80. With this solid foundation laid through series of efforts post 2019, the Union Territory of Jammu and Kashmir is now poised to take giant leap in its development. Few of the important provisions in this annual budget are as below

## **81. Economic Sector**

### **81.1 Agriculture and Allied sectors:**

- i. Establishment of 2,000 Kisan Khidmat Ghars (KKGs) for providing facilities to the farming community at their door step. Reinvigorating Agriculture and allied sectors through Holistic Agriculture Development

- Programme (HADP) by strengthening seed systems, boosting production and productivity, creating agri-business ecosystems and securing livelihoods through enhanced jobs and income creation.
- ii. Strengthening of Departmental Seed Multiplication Farms.
  - iii. Competitiveness Improvement of Agriculture and Allied Sectors project in Jammu and Kashmir (JKCIP) to be implemented with an estimated value of USD 100 million loan from International Fund for Agricultural Development (IFAD). The goal of the project is to contribute to the sustained increase in income of rural households by improving the competitiveness of farming operations.
  - iv. Implementation of all 29 projects approved under Holistic Agriculture Development Programme.
  - v. 20 agriculture and allied sector products have been identified, out of which 05 products (Saffron, Sulai Honey, Muskhbudgi Rice, Bhaderwah Rajmash and Udampur Kalari) have got geographical indication (GI) registration and rest are under process.
  - vi. Distribution of farm machinery benefitting 70,000 farmers.
  - vii. Production of designer plants for promotion of high density plantation and rejuvenation of orchards.
  - viii. 25,000 MTs of Controlled Atmosphere (CA) storage capacity to be added.
  - ix. Development of Chrysanthemum theme Park at Cheshmashahi, Srinagar.
  - x. 3,000 dairy units to be established providing direct employment to around 4,000 people.
  - xi. Increase in milk production from 25 to 45 lakh Metric Ton and increase in milk collection/chilling from 2.0 to 8.5 lakh Litres Per Day (LLPD) over a period of five years
  - xii. 100 satellite heifer rearing units will be established in the private sector.
  - xiii. 1,800 Pashu Sakhis will receive incentives for ration balancing for 6,00,000 cows and for the milk recording programme of 30,000 dairy cows.
  - xiv. 60,000 backyard poultry units will be established in rural areas.
  - xv. Hybrid fodder seed kits will be provided for 3,600 hectare of land.
  - xvi. 100 hydroponic fodder units and 60 silage-making units, along with 6 fodder depots to be established to ensure availability in fodder-deficient areas.

- xvii. Fish Production to be enhanced from 30,670 MT to 35,250 MT with technological interventions.

**For Agriculture and allied Sectors an allocation of about ₹2053.39 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹524.33 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **81.2 Rural Development and Panchayati Raj:**

- i. Under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 400 lakh mandays to be generated.
- ii. Under HIMAYAT training of around 7000 candidates to be completed.
- iii. 12,000 additional Self Help Groups (SHGs) to be formed during 2024-25.
- iv. 600 new panchayat ghars to be constructed under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) with 100% internet connectivity.
- v. 2.60 lakh mandays of training to Panchayati Raj Institution (PRI) members under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA).
- vi. 80,000 houses to be constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAY-G).
- vii. 06 Villages to have solid/liquid waste management facilities in order to become clean with litter and plastic free.
- viii. 26,000 hectare area to be treated with completion of 1,800 works under Integrated Watershed Management Programme (IWMP) during 2024-25.

**For Rural Sector, an allocation of about ₹3731.54 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25.**

### **81.3 Tourism and Culture:**

- i. New initiative for development of infrastructure and basic amenities in 12 off-beat tourist destinations, 6 each in Jammu and Kashmir divisions, with objective of enhancing tourism appeal and expanding local business and job opportunities.
- ii. Development of Keran as border tourist village.
- iii. Development of Tosamaidan and Sitharan circuits.
- iv. Development of Duggar Dani village at Samba with the traditional set up in the form of "mock village".
- v. Construction and installation of 130 meter (425 feet) high national flag mast at Patnitop.
- vi. Completion of revival and restoration of 75 identified heritage sites/cultural sites.
- vii. Establishment and operationalization of 8 cultural centers.
- viii. Development and modernization of Shri Pratap Singh (SPS) Museum Srinagar.
- ix. Promotion and propagation of sufism in Jammu and Kashmir through structured programmes including operationalization of state of art Suffiana School at Srinagar.
- x. Digitization of all libraries.

**For Tourism and Culture sector, an allocation of about ₹519.70 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹205.45 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **81.4 Forestry and Environment:**

- i. Planting of 190 lakh native trees and 100 lakh low cost greening interventions aimed to restore ecosystems, prevent soil erosion and enhance biodiversity.
- ii. All 78 urban Local bodies of Jammu and Kashmir to have at least one Nagar Van, Nagar Vatika or an Eco Park.

- iii. 10 lakh saplings of local, medicinal and economic importance species to be distributed among the farmers for planting to augment trees outside forests and improve livelihood.
- iv. Infrastructure at wetlands like Gharana, Hokersar and Shallbugh to be developed for promotion of eco-tourism.
- v. Establishment of Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (CAAQMS) in Jammu.
- vi. Implement of Van se Jal, Jal se Jeevan, an innovative water conservation techniques through water shed management approach, promote sustainable agricultural practices and revitalize traditional water bodies, including wetlands.
- vii. Conservation and rejuvenation of Wular Lake to enhance the livelihood of the local people, through ecotourism.
- viii. Enhancing avenues of livelihood generation through involvement of the Panchayat level Biodiversity Management Committees (BMCs) and integrating them with Self Help Groups (SHGs) registered with NRLM for sustainable collection and disposal of forest produce.

**For Forest sector, an allocation of about ₹186.45 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹52 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **81.5 Cooperative Sector:**

- i. Establishment of Micro Food Processing Units for creating employment opportunities, especially in rural areas.
- ii. Construction / Establishment of Mini Super Bazars at District / Village/ Block Level.
- iii. Construction of 6 Grain storage units in 6 districts which are deficit in grain storage facility under the Scheme “World’s Largest Grain Storage”.

**For Cooperative sector, an allocation of about ₹25 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹5 crore more than revised allocation of 2023-24.**



## 82. Social Sector

### 82.1 Health and Wellness:

- i. Two Cancer Institute's at Jammu and Srinagar to be made fully operational during 2024-25.
- ii. Enhancing DNB Seats to 400 thereby improving the availability of Specialists.
- iii. Health records to be saturated by creation of ABHA IDs for 1.35 crore population.
- iv. 100% screening of 30+ age population for hypertension and diabetes.
- v. Dialysis Services to be strengthened further at 16 existing facilities and 10 new health facilities.
- vi. AIIMS, Awantipora to be made functional by March, 2025.
- vii. New Nursing College at Handwara to be set-up.
- viii. Attainment of TB free status in all the remaining districts.

**For Health and Medical Education Sector, an allocation of about ₹1674.51 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25.**

### 82.2 Education Sector:

- i. 2,176 new Kindergartens to be established to attain saturation in all the 13,804 schools in phased manner.
- ii. Separate annual library grant ranging from ₹5,000 to ₹20,000 covering schools from Primary to Senior Secondary for purchase of books under Samagra Shiksha Abhiyan.
- iii. Only fortified rice to be served to about 8.95 lakh students at elementary level (I to VIII) under Mid-Day Meal Scheme for improving nutritional health of students.
- iv. Infrastructure of 389 schools to be upgraded under Pradhan Mantri Schools for Rising India (PM SHRI) Scheme.

- v. 3.50 lakh adults to be made literate under New India Literacy Programmer (NILP)
- vi. Scholarship @ ₹5,000/ student under Beti Anmol Scheme for BPL girl students.
- vii. 18,499 Schools to be provided sports equipment's with the financial implication of ₹16.04 crore.
- viii. 2,584 Schools to be provided ICT labs and Smart Classrooms.
- ix. 43 Robotic Labs and 30 Virtual Reality Labs to be established.
- x. Establishment of Science Centres in 100 Schools.
- xi. Vocational Education to be introduced in new 554 Schools.
- xii. Construction of 05 newly established colleges to be completed during 2024-25.
- xiii. Two hostel blocks, two science blocks and six additional lecture blocks in various colleges to be completed.
- xiv. 08 colleges to be accessed and accredited in the 2024-25.
- xv. 100% admission through Common University Entrance Test (CUET) e-Samarth across Jammu and Kashmir.

**For School and Higher Education Sector, an allocation of about ₹1,284.47 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹185.69 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **82.3 Social / Tribal Welfare:**

- i. All persons with disability to be covered under Nirmaya Health Insurance Scheme.

- ii. 04 Vatsalya Sadans to be operationalized for intellectually challenged person (boys/girls) two each in Jammu/Kashmir.
- iii. 653 Anganwadi Centres (AWCs) have been targeted for upgrading as Bal Vidyalayas.
- iv. 11 Shakti Sadan and 04 Sakhi Niwas to be established.
- v. 7,708 women beneficiaries with establishment of 1,502 units to be targeted under self-employment scheme
- vi. 14 Palash and 13 Parisha child care Institutes are targeted for modernization with state of the art facilities.
- vii. 250 small nature of tractor and link road connectivity to be provided to tribal population.
- viii. 80 schools to be transformed into smart schools in tribal areas.
- ix. Smart cards to be provided to migratory tribal population.
- x. Transit accommodations to be established for trans-human tribal population which includes accommodation for 150-200 families, community kitchens, medical dispensaries, veterinary dispensaries, community toilets and livestock yards.
- xi. 186 villages, having 500 schedule tribe population, to be covered under “Pradhan Mantri Adi Adarsh Yojana (PMAAGY)” scheme.
- xii. 10 Cluster Tribal Model villages to be completed in 2024-25.
- xiii. 10 milk villages are targeted to be completed during 2024-25.

**For Social and Tribal Welfare, an allocation of about ₹358.52 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹11.32 crore more than revised allocation of 2023-24.**

#### **82.4 Relief and Rehabilitation of Kashmiri Migrants:**

- i. Completion of construction of 1,500 flats as transit accommodation for Kashmiri Migrant employees during 2024-25.

- ii. Remaining 276 posts out of 6,000 posts under PM-Package for Kashmiri Migrants to be filled in 2024-25.

**For Relief and Rehabilitation of Kashmir Migrants an allocation of ₹1044.92 crore has been made under revenue and capital expenditure during 2024-25, which is ₹134.70 crore more than the revised allocation of 2023-24**

### **82.5 Sports and Youth Initiatives:**

- i. 75 lakh youth engagement in various sports events to be held at the Panchayat, Block, District, UT and National level during 2024-25.
- ii. 20 national sports events to be organized in 2024-25.
- iii. 200 playfields and 100 sports courts to be constructed.
- iv. Swimming pools to be completed at Moulana Azad Stadium, Jammu and Gindun Park Rajbagh, Srinagar.

**For Sports sector, an allocation of about ₹145.19 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹35.19 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **82.6 Skill Development, Youth Empowerment and Employment:**

- i. New initiative to create ecosystem for promotion of enterprises and self-employment, generate over 5 lakh opportunities for self-employment and expand investments through credit support.
- ii. New age courses to be introduced in 10 Industrial Training Institutes.
- iii. Placement drives for 1,000 pass outs to be organized in collaboration with big business and industrial establishments.
- iv. Training of 6,000 women Self Help Groups registered with NRLM to be completed
- v. Financial support through self-employment schemes like Seed Capital Fund Scheme, Youth Start-up Loan Scheme, National Minorities

Development and Finance Corporation, Women Entrepreneurship Programme and under Mission Youth schemes to be provided to youth to undertake self-employment ventures.

- vi. Outreach and counselling activities to be conducted for aspiring job seekers through Model Career Centers (MCCs).
- vii. Up skilling of youth through youth clubs.

**For Skill Development and Employment, an allocation of about ₹176.98 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹60.78 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **82.7 Food Civil Supplies and Consumer Affairs:**

- i. Additional 10 kg of rice per month to Priority Households will be provided under Prime Ministers Food Supplementation Scheme.
- ii. e-KYC of all beneficiaries under Public Distribution System to be completed.
- iii. Roll out of Smart PDS in Jammu and Kashmir.

**For Food and Civil Supplies sector, an allocation of about ₹445.25 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹65.79 crore more than revised allocation of 2023-24.**

## **83. Infrastructure Sector**

### **83.1 Power Sector:**

- i. Better availability of power which will give boost to tourism and Industries thus fulfilling the goal of no poverty, economic growth to provide sustainable jobs and promote equality.
- ii. Smart metering of all consumers.

- iii. Implementation of Loss Reduction works already in place. Majorly LT-AB Cabling work and removal of bare conductor to improve billing efficiency and bringing down the AT & C losses.
- iv. Implementation of underground cabling project to extend the Grid connectivity to Holy Shri Amarnath Ji cave on both the axis (Baltal and Pahalgam)
- v. Improvement of 105.00 km HT/LT line for smooth and uninterrupted power supply to its consumers.
- vi. Augmentation/Creation of 35.45 MVA Sub-Stations to give relief to Critically Overloaded Power Transformers and ensuring for availability of additional power supply to avoid frequent breakdown and load shedding.
- vii. Creation/Augmentation of 38,150 KVA Distribution Transformer sub-stations to improve voltage regulation of distribution network and enhance capacity of existing sub-stations.
- viii. Under segregation of critically overloaded 11 KV feeders, 55 Ckm are being segregated for enhanced feeder stability.
- ix. Replacement of 14,000 Ckm of dilapidated LT bare conductor by LT-AB cable to strengthen the LT networks and to stop the theft of power. This replacement of bare conductor by LT- AB cable coupled with installation of smart meters will help in reducing the AT & C losses.
- x. At 11 KV level, 5,351.53 Ckm of feeders to be renovated with new and better (thicker) conductor to reduce T & D losses.

- xi. At 66/11 KV and 33/11 KV Sub stations, 200 capacitor banks will be installed to improve the voltage profile at peak load hours and will reduce the MVA consumption.
- xii. 31 receiving stations (33/11kV) have been projected for capacity addition of 210.60 MVA.
- xiii. Providing of reliable power supply to the far-flung and remote areas of Gurez.
- xiv. 04 GSSs at 132 KV level will be constructed which will enhance capacity by 40 MVA during 2024-25, 100 MVA during 2025-26 and 90 MVA during 2026-27.
- xv. 16 GSSs at 132kV level will be augmented which will enhance capacity by 556 MVA during 2024-25 and 50 MVA during 2025-26.
- xvi. 06 GSSs at 220kV level will be augmented which will enhance capacity by 90 MVA during 2024-25 and 720 MVA by or before 2026-27.
- xvii. An addition of 3,014 MW installed capacity in phased manner till year 2026-27 with cumulative increase of design energy of 10,714.50 Million units per annum.

**For Power sector, an allocation of about ₹2020.67 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹698.28 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **83.2 Jal Shakti (Water Supply and Irrigation):**

- i. Out of 3,256 water supply schemes under Jal Jeevan Mission (JJM), 776 schemes have been completed and remaining 2,480 schemes have been targeted for completion for coverage of balance 4.26 lakh households

with Functional Household Tap Connections (FHTCs) to achieve 100% coverage under tap water connections.

- ii. NABL recognition of all 76 Sub Divisional level laboratories.
- iii. Roll out of Operation and Maintenance policy for rural water supply schemes.
- iv. Training of about 15,000 Nal Jal Mitras under NJMP through Skill Development Mission.
- v. 450 water supply schemes under languishing programme and 159 water supply schemes under National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) loan assistance are targeted for completion in 2024-25.
- vi. 225 flood control schemes to be completed, which will protect 1,467 hectare of land from erosion and flood threats.
- vii. 16 flood control projects under Flood Management and Border Area (FMBA) programme / River Management and Border Areas (RMBA) programme to be completed during current financial year.
- viii. Shahpur Kandi Dam project likely to be commissioned during current financial year, which will benefit Jammu and Kashmir with 1,150 cusecs of irrigation water facilities to 32,186 hectare of land in Kathua and Samba.
- ix. Balance work of Tawi Barrage to be completed during 2024-25.
- x. 197 minor irrigation schemes to be completed during 2024-25, which envisages creation of irrigation potential of 38,723 hectare.

**For Jal Shakti Department, an allocation of about ₹2661.96 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹1129.03 crore more than revised allocation of 2023-24.**



### **83.3 Housing and Urban Development:**

- i. 05 Sewerage Treatment Plants (STPs) with sewerage treatment of capacity of 65.33 MLD are under implementation.
- ii. Under AMRUT 2.0, UT Water Action Plan for 153 projects of 78 ULBS has been completed. This includes 99 projects for water supply connections aiming to provide 2.25 lakh new tap household connections. Also 50 projects for rejuvenation of water bodies to be undertaken.
- iii. Under Smart Cities Mission out of 309 projects, 223 projects have been completed and 86 project likely to be completed in 2024-25.
- iv. Pollution abatement of river Tawi by way of laying interception and diversion network at old city.
- v. Revamping of transport nagar Narwal Jammu and Parimpora Srinagar.
- vi. 100% source segregation of municipal solid waste by March 2025.
- vii. Development of Smart Integrated Satellite Township along Ring Road at Jammu and Srinagar.
- viii. Introduction of 200 e-buses under PM e-Bus Sewa scheme.
- ix. Pollution abatement projects of rivers Basentar at samba and Doodh Ganga at Srinagar/Budgam is being undertaken and the project Pollution abatement of River Devika at Udhampur to be completed.
- x. Western Foreshore Road along Dal Lake, Srinagar to be constructed.
- xi. Inter Model Station (IMS) in collaboration with NHAI to be developed at Katra.
- xii. Finalization of Master Plan of all 78 Cities/Towns.
- xiii. Development of Sewerage network of Houseboats in Dal-Nigeen Lake including sewerage network of hamlets inside lake.

- xiv. Construction of Modern Abattoirs at Gujjar Nagar and Dogra Hall Jammu.
- xv. Sewerage Scheme to be taken at Chrar-i-Sharief, Budgam.

**For Housing and Urban Development Sector, an allocation of about ₹2760.26 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹131.99 crore more than revised allocation of 2023-24.**

#### **83.4 Connectivity:**

- i. 5,000 Kilometres of road length to be black-topped during 2024-25 under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)/Cities and Towns scheme / Central scheme/Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)/National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) loan assistance/pothole free road scheme.
- ii. 194 new projects sanctioned at an estimated cost of ₹1023.42 crore under NABARD to be taken for execution during 2024-25.
- iii. ₹1000 crore new road and bridge projects to be taken up under NABARD loan assistance under RIDF Tranche XXX during 2024-25.
- iv. Completion of 60 ongoing bridges is targeted during 2024-25.

**For Road and Bridge Sector, an allocation of about ₹4061.74 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹118.87 crore more than revised allocation of 2023-24.**

#### **83.5 Industrial Development:**

- i. Rapid development of 46 new Industrial Estates to attract investment and create employment opportunities
- ii. Under Jammu and Kashmir Rural Employment Generation Programme (J & K REGP), 1,372 units are targeted to be setup during 2024-25.

- iii. New Start-up Policy to be introduced for creating entrepreneurship ecosystem.
- iv. Up-gradation of infrastructure in existing Industrial Estates.
- v. The Private Industrial Estate Development Policy to be revamped.
- vi. 324 units are expected to come into production this year having employment potential of 18,000 persons.

**For Industries and Commerce Sector, an allocation of about ₹534.62 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹138.36 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **83.6 Science and Technology:**

- i. 4,000 AC agriculture pumps to be replaced by Solar Pumps in phased manner under PM-KUSUM Component “C”.
- ii. Around 04 MW rooftop solar power plants to be installed on the government buildings. 22,494 Government buildings to be 100% solarised in phased manner.
- iii. 100 kw floating solar power plant to be installed in the Dal Lake, Srinagar for demonstration purpose to attract the tourists.
- iv. 5,000 improved biomass cook-stoves to be provided in the tribal areas to reduce indoor air pollution and fuel use.
- v. Land bank to be identified for development of solar parks.
- vi. Under Special Area Development Programme (SADP) tourist and religious places to be taken-up for complete solarization.
- vii. Solarization of all routes and camps of Shri Amarnath Ji Yatra.
- viii. Operationalization of Bio-Technology Park at Kathua.
- ix. Science talent Scholarships for Undergraduate and PG Students.
- x. Young Scientist Awards/Fellowships among the outstanding researchers.

**For Science and Technology Sector, an allocation of about ₹159.80 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹71.80 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **83.7 Transport Sector:**

- i. IDTR at Kot Bhalwal, Jammu likely to be completed and operationalized in 2024-25.
- ii. Institute of Inspection and Certification Centre (ICC) at Samba, Jammu likely to be completed in 2024-25.
- iii. Implementation of Vehicle Location Tracking Platform (VLTP) for safety of women in public transport vehicles.
- iv. Automated Testing Stations (ATSS) to be established for testing fitness of motor vehicles in private sector.
- v. Introduction of policy of Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) for carrying out dismantling and scrapping operations of vehicles for End of Life vehicles (ELVs) in a scientific manner
- iv. Construction of Modern Bus Terminal at TRC, Srinagar.

**For Transport Sector, an allocation of about ₹22 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is ₹8.11 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **84. Budget for 2024-25**

- i. The total gross receipts are estimated at ₹1,51,526 crore, including the provision for ways and means advances and over-draft of ₹33,136 crore. Given these receipts, the total gross expenditure is estimated to be ₹1,51,526 crore.
- ii. The total net budget estimates for the fiscal 2024-25 are ₹1,18,390 crore, excluding the provision for ways and means advances and overdraft. The expected revenue receipts are ₹98,719 crore and capital receipts are ₹19,671 crore. Similarly, the revenue expenditure is estimated to be ₹81,486 crore and capital expenditure to be ₹36,904 crore.

- iii. The own revenues both tax and non-tax are estimated to be ₹30,586 crore. In addition to this, ₹42,278 crore is to flow as central assistance and ₹12,502 crore as CSS/ PMDP to the Union Territory of Jammu and Kashmir.
- iv. Accordingly, the Jammu and Kashmir Appropriation Bill No (01) in respect of Budget Estimates for 2024-25 is proposed to be presented to authorize payment and appropriation of ₹1,51,525.7743 crore from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir.

**85. Fiscal Indicators**

- i. The tax/GDP ratio is projected at 7.91% for 2024-25 which is higher than the previous year of 6.56 %.
- ii. Fiscal deficit for the year 2024-25 is estimated to be 3.0%. This is substantially lower than 5.3% in 2023-24 (RE). This decrease has been possible due to the special financial assistance from the central government.
- iii. GDP for the year 2024-25 has been projected at ₹2,63,399 crore which shows a growth of 7.5 % over the previous year.

86. Mr. Speaker Sir, with these words, I commend the Budget for the financial year 2024-25 of the Union Territory of Jammu and Kashmir to this august House for consideration.